असम के माननीय राज्यपाल

श्री गुलाब चंद कटारिया जी का

अभिभाषण

पंचदश असम विधान सभा

5 फरवरी, बजट सत्र, 2024

असम विधान सभा के सम्मानित अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण,

असम विधानसभा के बजट सत्र 2024 के अवसर पर इस महान सदन को संबोधित करते हुए मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है। इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे यकीन है कि इस सत्र के दौरान विचार-विमर्श के जरिए शांति, प्रगति और समृद्धि की एक नई युग की शुरुआत होगी। साथ ही राज्य को जीवंत और प्रगतिशील राज्य के रूप में परिवर्तन हेतु एक रोडमैप तैयार करने पर सहायक सिद्ध होगा।

सरकार की एक्ट ईस्ट नीति -

सरकार की एक्ट ईस्ट नीति ने दक्षिण के (बांग्लादेश, भूटान और नेपाल) देशों के साथ अच्छे संबंध विकसित करने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, असम सरकार ने वाणिज्य और निवेश में अवसरों को उजागर करने, असम के उद्यमियों के बीच नेटवर्किंग के निर्माण के लिए 2023-24 में परिणाम-उन्मुख कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित करने की एक प्रमुख पहल की है। इससे आसियान (ASEAN) और अन्य पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध तथा शिक्षा और सीमा जागरूकता आदि क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करेगा।

इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार ब्रह्मपुत्र-मेकांग व्यापार और निवेश मंचों पर एक एकीकृत बहु-वर्षीय परियोजना के लिए अपने क्षेत्रीय भागीदार के रूप में मेकांग संस्थान के साथ सहयोग पर चर्चा कर रही है। एकीकृत परियोजना का उद्देश्य क्षेत्रीय और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने के लिए मेकांग देशों के साथ

व्यवसायिक संबंधों के माध्यम से एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। इससे असम में तेजी से आर्थिक विकास के माध्यम से विकासात्मक कार्य में सहायता होगा। इसके अलावा, आसियान और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एमएसएमई एकीकरण का समर्थन करके समावेशी और अधिक न्यायसंगत विकास का समर्थन करना है। तदनुसार, असम के कुल 200 एमएसएमई को मेकांग देशों की 400 कंपनियों के साथ सहयोग और व्यवसायिक संबंध बनाने का अवसर मिलेगा और उन्हें परियोजना से प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा।

"पावर्ड बाय पार्टनर" के रूप में, एक्ट ईस्ट पॉलिसी अफेयर्स डिपार्टमेंट ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के तीसरे संस्करण के आयोजन में ट्रेड एमएमएस संगठन के साथ सहयोग किया। इसका आयोजन 27, 28 और 29 अक्टूबर, 2023 को वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में किया गया था। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के दृष्टिकोण के साथ, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुलों का निर्माण करना और भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, पर्यटन और लोगों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना था।

उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान और तकनीकी शिक्षा विभाग शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम के लिए एक नीति तैयार करेगा। जिसमें, आसियान और बीबीएन (बांग्लादेश, भूटान और नेपाल) देशों के छात्र हमारे राज्य के इंजीनियरिंग, मेडिकल के साथ-साथ अन्य व्यावसायिक संस्थानों में अध्ययन कर सकेंगे।

सांस्कृतिक मामले -

पिछले वर्ष में हमारी सरकार द्वारा किए गए उल्लेखनीय प्रयासों को आपके साथ साझा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। 14 अप्रैल 2023 में, हमने 11,369 प्रतिभागियों की प्रस्तुति के साथ एक ही स्थान पर सबसे बड़े बिहू नृत्य का आयोजन किया। जिससे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इस कार्यक्रम में भारत के माननीय प्रधान मंत्री जी भी उपस्थित थे।

असम सांस्कृतिक महासंग्राम 2023-24 एक राज्य स्तरीय पहल है। इसका उद्देश्य राज्य के हर कोने से 6 अलग-अलग सांस्कृतिक श्रेणियों की प्रतिभाओं को उजागर करना है। इससे ग्राम पंचायत / वीसीडीसी / एमएसी/वार्ड और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा जिले से लेकर राज्य स्तर तक विभिन्न प्रतिस्पर्धा स्तरों पर अभिव्यक्ति के लिए एक मंच को बढ़ावा मिलेगा।

अक्टूबर 2023 में हमारी अमृत कलश यात्रा एकता का प्रतीक थी। इसके जरिए हर घर से मिट्टी एकत्र की गई थी और 2827 स्मारक पट्टिकाओं के साथ स्थानीय लोगों का सम्मान किया गया। साथ ही 2,18,977 पौधे लगाए गए। 18,80,146 से अधिक लोगों ने हाथ में मिट्टी/माटीडिया लेकर पंच प्राण प्रतिज्ञा ली और अभियान वेबसाइट पर सेल्फी अपलोड की।25,285 बहादुरों (सेवानिवृत्त) और मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों के परिवारों को सम्मानित किया गया। 270 विकास खंडों और शहरी स्थानीय निकायों में से प्रत्येक से एक अमृत कलश यात्री/स्वयंसेवक को 31 अक्टूबर, 2023 को अमृत कलश यात्रा के भव्य समापन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली ले जाया गया।

सांस्कृतिक मामलों का विभाग गांवों और नगरपालिका वार्डों में 259.70 करोड़ रुपये का निवेश करके 2597 नए पुस्तकालय बनाने का

कार्य कर रहे है, जो साहित्य के माध्यम से हमारे समुदायों को सशक्त बना रहा है।

एक भागीदार राज्य के रूप में, असम ने हरियाणा के कुरूक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 में गर्व से भाग लिया, जो सांस्कृतिक संवर्धन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है।

प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ-साथ ये पहल, असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए हमारे समर्पण को दर्शाती हैं।

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग -

पिछले कुछ वर्षों में, असम में स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया है। चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता अटूट रही है। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ नीचे उल्लेखित किया गया हैं।

चिकित्सा अवसंरचना का विस्तार:

वर्तमान में, हमारे पास विभिन्न सुपर स्पेशलिटी विषयों में कुल 1500 एमबीबीएस सीटों, 722 पीजी सीटों और 44 डीएम/एम सीएच सीटों के साथ 12 पूर्ण सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। इस शैक्षणिक वर्ष में, हमें तिनसुकिया में एक नए मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है, और 2025 में चराइदेव, बिश्वनाथ और कामरूप (महानगर) जिले में तीन और मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया जाएगा।

करीमगंज, गोवालपारा, तामुलपुर, बोंगाईगांव, धेमाजी, मोरीगांव, गोलाघाट और शिवसागर में एसओपीडी/आईएफए के तहत अतिरिक्त 08 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य चल रहा है। मोरीगांव और लखीमपुर में दो डेंटल कॉलेज प्रगति पर हैं, जो चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं।

जोरहाट और कोकराझार में 02 (दो) नए नर्सिंग कॉलेजों का शैक्षणिक सत्र वर्तमान सत्र 2023 में शुरू हुआ। बजट घोषणा के अनुसार दीफू, लखीमपुर, धुबरी, नगांव, नलबाड़ी, तेजपुर और बरपेटा में 07 (सात) नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की गई है।

सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और अस्पताल:

पीएमएसएसवाई के तहत, एएमसी डिब्रूगढ़ और जीएमसीएच गुवाहाटी में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और जीएमसीएच से जुड़े सुपर स्पेशलिटी अस्पताल "सीएन सेंटर" पूरी तरह कार्यात्मक हैं। इसके अलावा, भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने मेडिकल कॉलेजों सहित विभिन्न स्थानों में 7 (सात) कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन किया था और अन्य 07 (सात) कैंसर देखभाल केंद्र का निर्माण पूरा होने वाला है।

स्वास्थ्य अनुसंधान:

असम सरकार ने असम एडवांस्ड हेल्थकेयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट (एएएचआईआई) के कार्यान्वयन के लिए आईआईटी-गुवाहाटी के साथ एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी शुरू की है। इसकी कल्पना 500 बिस्तरों वाले अस्पताल के साथ एक अत्याधुनिक अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई है। जहां डॉक्टर, इंजीनियर और शोधकर्ता स्वास्थ्य क्षेत्र में नई

प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। परियोजना की आधारशिला अप्रैल, 2023 में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा रखी गई थी और यह हमारी स्वास्थ्य सेवा यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

स्वास्थ्य बीमा:

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत, राज्य 10.00 लाख लाभार्थियों को कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करने की उपलब्धि हासिल करने में सक्षम रहा है।

वर्ष 2018 में इसकी शुरुआत के बाद से, 4 लाख से अधिक लाभार्थियों को 588 करोड़ रुपये के कैशलेस उपचार की राशि वर्ष 2023 के दौरान बढ़ा दी गई है। एबी-पीएमजेएवाई और एनएफएसए के तहत 30 लाख परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का कैशलेस चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के पात्र हैं।

राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर, 2023 को आयुष्मान असम - मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना (AA-MMJAY) शुरू की है, जिसके माध्यम से अन्य 28 लाख परिवार भी अब योजना के तहत कैशलेस उपचार के लिए पात्र हैं। इस प्रकार, एबी-पीएमजेएवाई और एए-एमएमजेएवाई के अभिसरण ने लगभग 1.98 करोड़ लाभार्थियों वाले 58 लाख परिवारों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये के कैशलेस उपचार के लिए पात्र होने में सक्षम बनाया है।

राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन आईटी पोर्टल के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों की चिकित्सा

प्रतिपूर्ति के लिए आयुष्मान असम - मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना (एए-एमएमएलएसवाई) शुरू की। इससे चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए प्रसंस्करण समय कम हो जाएगा और सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक सुचारु और निर्बाध प्रतिपूर्ति प्रक्रिया सुनिश्चित होगी।

नीतिगत पहल:

चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख नीतिगत निर्णय पेश किए गए हैं। संकाय सदस्यों के लिए डीएसीपी योजना, पीजी के बाद सेवारत डॉक्टरों के लिए बांड अवधि को घटाकर एक वर्ष कर दिया गया है। प्रवेश स्तर के संकाय सदस्यों की कैंपस भर्ती एक मजबूत और कुशल स्वास्थ्य सेवा कार्यबल सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रवेश स्तर के पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा में वृद्धि, मेडिकल कॉलेजों के संकायों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि और असम एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने में योगदान देता है। इनके अलावा, राज्य में मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टरों के वृत्तिका में 15% की बढ़ोतरी की गई है और राज्य सरकार के स्कूलों/कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एमबीबीएस की 5% सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके अलावा, मोरान, मटक, ताई अहोम, चुटिया और कोच राजबंशी समुदायों में से प्रत्येक के लिए 03 (तीन) एमबीबीएस सीटें बढ़ाई गई हैं।

असम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी (एएचआईडीएमएस) के तहत परियोजनाएं:

राज्य सरकार जेआईसीए द्वारा वित्त पोषित असम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना (एएचएसएसपी) (परियोजना लागत

3800 करोड़ रुपये) और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित असम राज्य माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल पहल सेवा वितरण परिवर्तन (एएसएसआईएसटी) परियोजना जैसी परियोजनाओं को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रही है। परियोजना लागत 2510.64 करोड़ रुपये है।

जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) द्वारा वित्त पोषित असम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना: परियोजना का प्रमुख घटक छह (6) मेडिकल कॉलेजों (सिलचर, तेजपुर, जोरहाट, बरपेटा, दीफू और लखीमपुर) में सुपर स्पेशियलिटी विंग का निर्माण करना है।

चयनित जिला अस्पतालों में बुनियादी ढांचे में सुधार, समर्पित प्रशिक्षण, निगरानी, प्रशासनिक केंद्र, स्वास्थ्य भवन, चिकित्सा कर्मचारियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली में सुधार किया जाएगा। राज्य के चिकित्सा संस्थानों को महत्वपूर्ण उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 3797.78 करोड़ रुपये है। ऋण 27 जनवरी 2023 से प्रभावी किया गया है।

विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सेवा वितरण परिवर्तन के लिए असम राज्य माध्यमिक स्वास्थ्य सेवा पहल (ASSIST) परियोजना: परियोजना का प्रमुख घटक 2.5 वर्षों के लिए परिचालन लागत सहित 10 नए जिला अस्पतालों का निर्माण और 25 स्वास्थ्य सुविधाओं के मौजूदा बुनियादी ढांचे की कार्यक्षमता में सुधार करना है। परियोजना की कुल लागत 2510 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के लिए ऋण समझौते पर 19 सितंबर 2023 को हस्ताक्षर किए गए थे।

सर्वोत्तम प्रथाएँ और नवाचार:

प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए, राज्य सरकार ने सभी निदेशालयों में ई-ऑफिस को सफलतापूर्वक लागू किया है, और सभी खरीद गतिविधियों के लिए GeM पोर्टल का उपयोग किया जाता है। बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की शुरूआत और विकासात्मक गतिविधियों के लिए सीएसआर फंड जुटाना पारदर्शिता और दक्षता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

स्वास्थ्य उपकरण खरीद:

राज्य सरकार विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में सीटी, एमआरआई, कार्डियो कैथ लैब, पीईटी-सीटी मशीन और गामा-कैमरा की स्थापना के साथ उन्नत चिकित्सा उपकरणों में लगातार निवेश कर रही है। इसके अतिरिक्त, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भंडारण संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से महामारी की स्थिति के दौरान महत्वपूर्ण चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास चल रहे हैं।

आयुष क्षेत्र विकास:

भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के महत्व को पहचानते हुए, आयुष क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। राज्य सरकार ने माजुली और दुधनोई में दो नए 50 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पतालों का उद्घाटन किया है, जिन्हें राष्ट्रीय आयुष मिशन, असम के तहत क्रियाशील किया गया है।

भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने कोकराझार, बक्सा, मोरीगांव और कलियाबोर में 50 बिस्तरों वाले 4 (चार) आयुष

अस्पताल, दीफू में 30 बिस्तरों वाले 1 (एक) आयुष अस्पताल और बजाली में 1 (एक) 10 बिस्तरों वाला आयुष अस्पताल स्थापित करने की मंज़ूरी दी है। असम लोक निर्माण विभाग (एपीडब्ल्यूडी) (भवन) ने कोकराझार और बास्का के लिए ई-टेंडर जारी किया है। शेष अस्पतालों के लिए ई-निविदा थोड़े समय के भीतर जारी होने की उम्मीद है। इसके अलावा, आयुष सेवाओं को लोगों के करीब लाने के लिए 100 आयुष औषधालय का निर्माण प्रक्रिया में हैं।

राष्ट्रीय आयुष मिशन, असम के तहत एक जीवधारा नामक विशेष कार्यक्रम यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को योग प्रदान करना लॉन्च किया गया है और राज्य भर में 6 (छह) केंद्र सफलतापूर्वक चल रहे हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र -

एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, हमारी सरकार ने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ शुरू की हैं, अर्थात् - "स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी उम्र के लोगों के लिए कल्याण को बढ़ावा देना"।

विभाग ने सेवा प्रदाताओं और सेवा वितरण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए स्वास्थ्य सेवा उत्सव शुरू किया है। पहला भाग 6 से 8 अप्रैल 2023 तक और दूसरा भाग 20 से 22 नवंबर तक आयोजित किया गया था। इसने भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) 2022 मानकों को प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, डायग्नोस्टिक्स, सेवाओं आदि के वास्तविक अंतर का आकलन करने में मदद की है।

मुख्यमंत्री निःशुल्क निदान कार्यक्रम के तहत कुल 14,03,461 मरीजों को निःशुल्क सीटी स्कैन सेवाओं का लाभ मिला। 30 नवंबर 2023 तक 35,48,097 मरीजों को मुफ्त एक्स-रे सेवाओं का लाभ मिला। असम सरकार चाय बागान अस्पतालों सहित मुफ्त दवा सेवाओं के तहत आवश्यक दवाएं मुफ्त प्रदान कर रही है।

"असम के चाय बागान क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं के लिए मजदूरी मुआवजा योजना" के तहत चाय बागान की गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। योजना का उद्देश्य चाय बागान क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण प्रदान करना है। बजट 2023-24 में राशि को 12,000/- रुपये से बढ़ाकर 15,000/- रुपये करने का निर्णय लिया गया है।

व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किया गया है। राज्य में कुल 4,480 एबी-एचडब्ल्यूसी को क्रियाशील बनाया गया है।

SEWA SETU के कार्यान्वयन पर 26 मार्च 2023 से जन्म और मृत्यु का मैन्युअल पंजीकरण बंद कर दिया गया है। जुलाई 2023 तक 98.09% जन्म और 93.34% मृत्यु दर्ज की गई है।

हाल ही में, माजुली और दुधनोई में जुलाई, 2023 से 2 नए 50 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पतालों को क्रियाशील बनाया गया है।

भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने कोकराझार, बक्सा, मोरीगांव और कलियाबोर में 50 बिस्तरों वाले 4 आयुष अस्पताल, दीफू

में 30 बिस्तरों वाले 1 आयुष अस्पताल और बजाली में 10 बिस्तरों वाले 1 (एक) आयुष अस्पताल स्थापित करने की मंजूरी दी है।

ईट राइट इंडिया पहल के तहत एफएसएसएआई ने असम राज्य को अनुदान दिया है। इसके तहत FSSAI 2023-24 से सहायता के रूप में कुल 940.88 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है।

असम सरकार टीकाकरण के माध्यम से पूर्ण टीकाकरण कवरेज में सुधार करके राज्य में बाल मृत्यु दर और रुग्णता को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। 5 वर्ष से कम उम्र के सभी छूटे हुए और ड्रॉप-आउट बच्चों और गर्भवती महिलाओं की पहचान करने और टीकाकरण करने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 को शुरू किया गया है। भारत सरकार ने इस वर्ष 2023 में गहन मिशन इंद्रधनुष (आईएमआई) 5.0 के तीन दौर आयोजित किए हैं और तीन दौर में कुल 2,98,617 लाख लाभार्थियों को टीका लगाया गया था।

पीसी-पीएनडीटी के तहत, जेनेटिक परामर्श केंद्र, जेनेटिक प्रयोगशाला, जेनेटिक क्लिनिक, इमेजिंग और यूएसजी क्लिनिक या अल्ट्रासाउंड और इमेजिंग मशीन या स्कैनर वाले केंद्र के लिए ईओडीबी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण सेवा प्रणाली शुरू की गई है। वर्ष 2023 के दौरान जिलों के लिए सभी मौजूदा यूएसजी क्लीनिकों की मैपिंग पूरी की गई। पीसी और पीएनडीटी के तहत पंजीकरण प्राप्त करने पर नए क्लीनिकों की भी मैपिंग की गई।

राजस्व और आपदा प्रबंधन क्षेत्र - मिशन बसुंधरा 2.0

लोगों के सुविधा के लिए, अगली पीढ़ी की भूमि संबंधी सेवाओं की पेशकश करते हुए 14 नवंबर, 2022 को मिशन बसुंधरा 2.0 लॉन्च

किया गया था। आवेदन 2 अप्रैल, 2023 तक प्राप्त किए गए थे और निपटान की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 तय की गई थी। मिशन बसुंधरा 2.0 में इस प्रकार की सेवाएं प्रदान की गई हैं - (i) वार्षिक पट्टा (एपी) भूमि का निपटान जो अतीत में हस्तांतरित किया गया है भूमि नीति के अनुसार पात्र व्यक्तियों को स्थायी, विरासत योग्य और हस्तांतरणीय अधिकार देने की दृष्टि से, (ii) निपटान वीजीआर/पीजीआर भूमि (iii) अधिभोग किरायेदारों को स्वामित्व अधिकार, (iv) खास सरकार और अधिकतम अधिशेष भूमि का निपटान, (v) आदिवासी समुदायों की वंशानुगत भूमि का निपटान (vi) स्वदेशी उत्पादकों को विशेष खेती के लिए भूमि का निपटान। इसके तहत, कुल आवेदन 13,39,605 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से एसडीएलएसी और असम सरकार की जांच और अनुमोदन के बाद (31-दिसंबर-2023 तक) 2,26,934 आवेदकों को 'निपटान के प्रस्ताव' जारी किए गए हैं।

मिशन बसुंधरा 2.0 के दौरान, मौजूदा नीतियों के अनुसार स्वदेशी, भूमिहीन परिवारों को भूमि की सुरक्षा प्रदान करना है। सभी शहरी क्षेत्रों (नगरपालिका बोर्डों) में प्रीमियम संरचना के आधार पर क्षेत्रीय मूल्य के 100%, 30% और 10% तक किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए निपटान प्रीमियम गृहस्थी और कृषि दोनों उद्देश्यों के लिए सामान्य समय में 500/- रुपये प्रति बीघे के बजाय केवल 100/- रुपये प्रति बीघे निर्धारित किए है। इसके अतिरिक्त, प्रीमियम के आस्थगित भुगतान की भी सुविधा है, जिसमें 30% का अग्रिम प्रारंभिक भुगतान और बाकी का भुगतान 5 वर्षों की अवधि में किया जाना है।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, विकलांग व्यक्तियों, जिनके पास आय का कोई नियमित स्रोत नहीं है, विधवाओं जिनके परिवार में कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है और स्वदेशी भूमिहीन कृषकों के लिए मिशन बसुंधरा रियायतों के ऊपर 25% की दर से अतिरिक्त रियायत उपलब्ध कराया है।

मिशन बसुंधरा 2.0 के तहत छह सेवाओं के लिए स्वदेशी एसटी, एससी, ओबीसी और एमओबीसी श्रेणी के आवेदकों से 6,89,155 आवेदन प्राप्त हुए है। जिनमें से जांच के बाद 1,90,387 आवेदकों को 'ऑफर ऑफ सेटलमेंट' दिया गया। (31 दिसंबर, 2023 तक)।

स्वामित्व के तहत गैर-कैडस्ट्रल गांवों में सर्वेक्षण और निपटान की पेशकश

SVAMITVA योजना के तहत, विस्तृत सर्वेक्षण के लिए बिना सर्वेक्षण वाले गैर-संवर्गीय गांवों को और वहां के निवासियों को लिया गया है। आधुनिक और वास्तविक समय रिकॉर्ड वाले इन गांवों को भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए मॉडल गांवों के रूप में स्थापित किया जाएगा।

निवासियों को स्वामित्व अधिकार देने, उन्हें आर्थिक लाभों, सरकारी लाभों से जोड़ने के लिए SVAMITVA के तहत गैर-संवर्गीय गांवों का सर्वेक्षण चल रहा है। 849 गांवों में ड्रोन उड़ान पूरी हो गई है और 261 गांवों में विस्तृत सर्वेक्षण पूरा हो गया है (18-दिसंबर-2023 तक)। पूरा हो चुके गांवों में जल्द ही प्रॉपर्टी कार्ड वितरण शुरू होने की उम्मीद है।

हाइब्रिड प्रौद्योगिकी का उपयोग कर 18789 गांवों का पुनर्सर्वेक्षण

भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने और इसे जमीनी हकीकत का दर्पण बनाने के लिए 18789 गांवों का तीन चरणों में पुन: सर्वेक्षण शुरू किया गया है। अंतिम डेटा को भू-नक्शा में अपलोड किया जाएगा और भूमि रिकॉर्ड और ULPIN (यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर) पीढ़ी के वास्तविक डिजिटलीकरण के लिए RoR के साथ एकीकृत किया जाएगा। कैडस्ट्राल गांवों के पुन: सर्वेक्षण से स्वामित्व को स्पष्ट करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस):

यह एक नागरिक केंद्रित सॉफ्टवेयर है जिसे ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण, प्रासंगिक दस्तावेजों को अपलोड करने और दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए एसआरओ के साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह नागरिकों द्वारा ऑनलाइन दस्तावेज़ प्रविष्टि, ऑनलाइन संपत्ति मूल्यांकन और स्टांप शुल्क गणना जैसी सेवाएं प्रदान करता है।

एनजीडीआरएस परियोजना 14 नवंबर, 2022 को कामरूप और दरांग जिलों के 6 (छह) पंजीकरण कार्यालयों में पायलट आधार पर शुरू की गई थी। सफल परीक्षण के बाद, अब एनजीडीआरएस को 31-मार्च-2024 से पहले राज्यव्यापी रोल-आउट करने की योजना है।

ई-स्टाम्प :

असम सरकार ने 1 जुलाई, 2023 से भौतिक गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्रों को प्रतिस्थापित करके 100% ई-स्टाम्प की शुरुआत की है। सभी भौतिक स्टांप पेपर विक्रेताओं को स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया

लिमिटेड (एसएचसीआईएल) के तहत ई-स्टांपिंग केंद्रों के लिए लाइसेंस दिया जाता है। ई-स्टाम्प बिक्री केंद्र स्थापित करने के लिए इच्छुक भौतिक स्टाम्प विक्रेताओं को ₹ 1.00 लाख की एकमुश्त पुनर्वास राशिप्रदान की जाएगी।

असम सरकार के एक अंग के रूप में, राजस्व एवं डीएम (आपदा प्रबंधन) विभाग राज्य के भीतर प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ मानव निर्मित आपदाओं के दौरान आपात स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

एएसडीएमए ने सुरक्षित और लचीले असम के निर्माण के लिए तैयारी, प्रतिक्रिया और शमन पहलुओं की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं।

इन गतिविधियों में आपदा प्रतिरोधी समुदाय के निर्माण की दिशा में प्रतिक्रिया और राहत उपायों के रूप में प्रभावित परिवारों को जन केंद्रित सेवा वितरण शामिल है। एएसडीएमए ने प्रौद्योगिकी संचालित तैयारियों के साथ-साथ आपदाओं के दौरान प्रतिक्रिया के रूप में खतरे की निगरानी और निगरानी के लिए यूएवी का अधिग्रहण किया है।

एएसडीएमए ने असम में बाढ़ और कटाव के जोखिम को कम करने की दिशा में आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए बेहतर जल संसाधन प्रबंधन का समर्थन करने के लिए एफआरईएमएए और जल संसाधन विभाग के साथ एक सहयोगी विश्व बैंक वित्त पोषित परियोजना "असम एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन परियोजना (एआईआरबीएमपी)" शुरू की है। यह परियोजना असम को जल संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद करेगी जो सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय प्राथमिकताओं को संतुलित करेगी और असम को आपदा से निपटने में सक्षम बनाएगी।

भूमि किसी भी समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, विशेषकर उन मूल निवासियों के लिए जिनका अपनी पैतृक भूमि से गहरा संबंध होता है। हालाँकि, असम में कई मूल निवासियों को भूमिहीनता की समस्या का सामना करना पड़ता है, जो उनकी आजीविका, पहचान और गरिमा को प्रभावित करता है। इस मुद्दे को हल करने के लिए, असम के राजस्व और डीएम (सेटलमेंट) विभाग ने स्वदेशी भूमिहीन परिवारों और विभिन्न संस्थानों और समाजों को भूमि बंदोबस्त और आवंटन देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

हमारी सरकार ने राजस्व एवं डी.एम. (सर्वेक्षण एवं निपटान) विभाग के तहत शहरी क्षेत्र में 1405 स्वदेशी भूमिहीन परिवारों को भूमि बंदोबस्ती और विभिन्न संस्थानों और समाजों के 614 प्रस्तावों को भूमि आवंटन और वार्षिक पट्टे को आवधिक पट्टा / आवंटन प्रमाण पत्र को आवधिक पट्टा में परिवर्तित किया है। विभाग ने प्रस्तावों के निस्तारण के लिए एक समग्र रणनीति अपनाई है, जो मिशन सद्भावना के अनुरूप है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग -

विभाग ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत 7.75 करोड़ श्रम दिन के लक्ष्य के मुकाबले 7.43 करोड़ श्रम दिन सृजित करने के लक्ष्य का 95.95% हासिल किया गया है।

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 29 दिसंबर 2023 तक 2020.42 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इस योजना के तहत मजदूरी 229/- रुपये से बढ़ाकर 238/- रुपये प्रति दिन कर दी गई है। साथ ही, चालू वित्तीय वर्ष में 15 दिनों के भीतर उत्पन्न वेतन भुगतान का 98.92% बनाए रखते

हुए मजदूरी के समय पर भुगतान में सुधार किया गया है। राज्य ने मनरेगा के तहत पूर्ण कार्यों की 96.2% जियो-टैगिंग पूरी कर ली है।

असम में अमृत सरोवर का निर्माण पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मत्स्य पालन विभाग और मुख्यमंत्री समग्र ग्राम उन्नयन योजना के साथ अभिसरण मोड पर किया गया है।

भारत सरकार के अनुसार असम का लक्ष्य 2625 अमृत सरोवर था, लेकिन दिनांक 29/12/2023 तक बीआईएसएजी-एन के अनुसार 2848 अमृत सरोवर की खुदाई (108.50%) पूरी हो चुकी है।

कैलेंडर वर्ष के दौरान, असम को कुल 8,805.28 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसमें केंद्र के हिस्से से 7,924.75 करोड़ रुपये और राज्य के हिस्से से 880.52 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस अवधि में राज्य ने 9,138.44 करोड़ रुपये का उपयोग किया हा।

असम के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण 2023-24 के दौरान, पीएमएवाई-जी के छूटे हुए लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराने के लिए एक राज्य प्रमुख योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (एमएमएवाई-जी) की घोषणा की गई थी।

मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (MMAY-G):

ए) असम के माननीय वित्त मंत्री द्वारा राज्य की प्रमुख योजना की घोषणा बजट भाषण 2023-2024 के दौरान की गई थी। इसे 21 दिसंबर 2023 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित की गई। इस योजना का उद्देश्य पीएमएवाई-जी के तहत छूटे हुए लाभार्थियों को घर प्रदान करना है। राज्य में 1,30,000 पात्र लाभार्थियों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा।

बी) चयनित लाभार्थियों में से 10% यानी 13,000 घर चाय बागान क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जाएंगे।

सी) एमएमएवाई-जी के तहत, पात्र लाभार्थियों को पक्का घर बनाने के लिए 1.30 लाख रुपये दिए जाएंगे।

यह राशि डीबीटी मोड के माध्यम से 3 किस्तों में हस्तांतरित किया जाएगा और लाभार्थी मनरेगा से 95 व्यक्ति दिवस के अकुशल श्रम का हकदार होगा।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी):

केंद्र प्रायोजित योजना- एनएसएपी के तहत, इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न योजनाओं - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय में कुल 7,78,431 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)। इसके अलावा, 2274 लाभार्थी हैं जो पहले ही राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 20,000/- रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता से लाभान्वित हो चुके हैं।

स्वाहिद कुशल कोंवर सर्वजनिन बृद्ध पेंशन योजना:

यह योजना असम सरकार द्वारा 2018-19 में उन सभी वरिष्ठ नागरिकों को कवर करने के लिए शुरू की गई थी, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) के दायरे से बाहर हैं। गरीबी रेखा से नीचे हों या ऊपर, प्रत्येक बुजुर्ग नागरिक 250/- रुपये मासिक पेंशन पाने का हकदार है। वर्तमान में इस योजना के तहत 12,11,334 लाभार्थी हैं।

इंदिरा मिरी सार्वजनीन विधवा पेंशन योजना 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की सभी विधवा लाभार्थियों को कवर करने के लिए 2020 में शुरू की गई थी और 2 लाख से अधिक लाभार्थी पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं। यह योजना को अप्रैल, 2023 से ओरुनोडोई 2.0 में शामिल किया गया है और इन सभी लाभार्थियों को अब प्रति माह 1250/- रुपये मिलेंगे।

25 अगस्त, 2023 को माननीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित योजना 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना' (IGNWPS) के तहत विधवा लाभार्थियों को मासिक के साथ 950/- रुपये का राज्य अंशदान (टॉप-अप) प्रदान करने का निर्णय लिया है। मौजूदा पेंशन 300/- रुपये है और यह निर्णय दिसंबर 2023 से लागू हो गया है। इससे कुल 1,13,544 विधवा लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।

असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एएसआरएलएम)

आज तक असम के 34 जिलों और 219 ब्लॉकों में 3.46 लाख एसएचजी (स्वयं सहायता समूह) के तहत 38.97 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को संगठित किया गया है। 3.29 लाख एसएचजी को 53,271 लाख रुपये से अधिक का रिवॉल्विंग फंड (आरएफ) प्रदान किया गया है। आजीविका संवर्धन और सुदृढ़ीकरण के लिए लगभग 1.90 लाख एसएचजी को 97839 लाख रुपये की सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) प्रदान की गई है। संभावित प्राकृतिक आपदा और ऐसी अन्य आपदाओं का आकलन करते हुए, लगभग 11625 वीओ को लगभग 15734.16 लाख को भेद्यता न्यूनीकरण निधि (वीआरएफ) प्रदान की गई है। आज तक कुल मिलाकर लगभग 5.37 लाख एसएचजी (दोबारा खुराक सहित) ने बैंकों से कुल 10,091.31 करोड़ रुपये का ऋण लिया है।

"लखपति महिला किशन" पहल के तहत एएसआरएलएम ने लगभग 7.0 लाख लाखपति एसएचजी सदस्यों को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया है। एसएचजी सदस्यों ने वित्त वर्ष 23-24 के दौरान राज्य में वृक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार की एक पहल "अमृत बृखा आंदोलन" के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान में भी सक्रिय रूप से भाग लिया है।

उच्च शिक्षा क्षेत्र -

उच्च शिक्षा विभाग विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के माध्यम से उच्च शिक्षा के विस्तार एवं गुणवत्ता विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारी सरकार इन संस्थानों के बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ नए विश्वविद्यालयों, कॉलेजों की स्थापना और उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए मौजूदा कॉलेजों में अतिरिक्त स्ट्रीम शुरू करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करा रही है। सरकार ने छात्रों के हित और लाभ के लिए उच्च शिक्षा के तहत कुछ नई योजनाएं भी शुरू की हैं।

जिन बीपीएल छात्रों के माता-पिता की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये या उससे कम है, उन्हें फीस माफी के लिए 18387.32 लाख रुपये की राशि जारी की गई है और इस योजना के तहत 329612 छात्र लाभान्वित हुए हैं।

वर्ष 2022 के एचएस परीक्षा में प्रथम श्रेणी हासिल करने वाली 35800 लड़कियों और 75% और उससे अधिक अंक पाने वाले लड़कों को डॉ. बनिकांता काकाती पुरस्कार के तहत स्कूटर वितरित किए गए हैं। सरकार ने इस योजना के लिए 25411.07 लाख रुपये जारी किए हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान, 22 पदधारियों को 8000/- रुपये की दर से साहित्यिक पेंशन प्रदान की गई थी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू

विश्वविद्यालय में श्रीमंत शंकरदेव चेयर की शुरुआत की गई है। इसके लिए 1010.00 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

7 सरकारी मॉडल कॉलेज अर्थात् सरकारी मॉडल कॉलेज, बालीपारा, सोनितपुर, सरकारी मॉडल कॉलेज सामागुरी, नागांव, सरकारी मॉडल कॉलेज बक्सा, सरकारी मॉडल कॉलेज डिबलोंग, दिमा हसाओ, सरकारी मॉडल कॉलेज बाघबार, बारपेटा, सरकारी मॉडल महिला कॉलेज, चेंगा, बारपेटा, सरकारी मॉडल महिला कॉलेज बिलासीपारा, धुबरी कार्य करना प्रारंभ कर दिया है।

नए इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक:

एनआईडीए के तहत बोंगाईगांव, बेहाली और सुआलकुची में 6 (छह) नए इंजीनियरिंग कॉलेजों और रूसा के तहत नलबाड़ी, नागांव, उदलगुरी में निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन हैं और एसओपीडी के तहत हाजो, माजुली और तिंगखोंग में अन्य 8 (आठ) नए पॉलिटेक्निक का निर्माण कार्य चल रहा है। सीएसएस के तहत दरांग, कार्बी आंगलोंग, नागांव, धुबरी और दिमा हसाओ में भी प्रक्रिया चल रही है।

असम सरकार ने राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद (एससीटीई), असम द्वारा प्रदान किए जाने वाले इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा को उच्च माध्यमिक योग्यता (10+2) और एक वर्ष की शैक्षिक योग्यता के बराबर अधिसूचित किया है। इससे छात्र उन रोजगार के लिए आवेदन कर सकेंगे जहां न्यूनतम योग्यता हायर सेकेंडरी है। ये छात्र आईआईटी, आईआईआईटी, एनआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसे प्रीमियम

संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए जेईई प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने के भी पात्र होंगे। उत्तीर्ण डिप्लोमा छात्र भी सीधे द्वितीय वर्ष में बीएससी कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे।

असम सरकार ने असम के इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक में ओबीसी/एमओबीसी आरक्षण को मौजूदा 15% से बढ़ाकर 27% करने की मंजूरी दे दी है। ओबीसी आरक्षण में वृद्धि के अनुरूप, 6 समुदायों - टी ट्राइब्स, मोरान, मटक, ताई-अहोम, चुटिया और कोच राजबंशी के उम्मीदवारों के लिए असम के इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक में आरक्षित सीटों में वृद्धि भी सुनिश्चित की गई है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) शिक्षा मंत्रालय, सरकार के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। भारत सरकार का लक्ष्य उच्च शिक्षा तक पहुंच, उत्कृष्टता और समानता सुनिश्चित करना है, जिसे वर्ष 2013-14 से राज्य में लागू किया जा रहा है। सुदूरवर्ती एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रूसा चरण-1 के दौरान यूजीसी द्वारा चिन्हित राज्य के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 12 जिलों में कुल 12 मॉडल डिग्री कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 8 को कार्यात्मक रूप से चालू की गई है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग -

जल जीवन मिशन 15 अगस्त, 2019 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में अर्थात निर्धारित गुणवत्ता का न्यूनतम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है।

स्वच्छता क्षेत्र (एसबीएम-जी)

बीएलएस 2012 के अनुसार 5 मार्च 2019 को असम को ओडीएफ राज्य घोषित किया गया था। सभी के लिए स्वच्छता की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, नए विकसित परिवारों, विस्थापित आबादी और 2012 बेसलाइन सर्वेक्षण में शामिल नहीं किए गए लोगों को आईएचएचएल प्रदान करने की पहल की गई है। ऐसे में लेफ्ट आउट ऑफ बेसलाइन (एलओबी) और नो वन लेफ्ट बिहाइंड (एनओएलबी) के तहत शत-प्रतिशत शौचालय निर्माण का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। और नए उभरते घरों की श्रेणी के तहत 02.01.2024 को आईएमआईएस के अनुसार 196003 आईएचएचएल का निर्माण किया गया है। इसके अलावा आज (02.01.2024) तक सार्वजनिक स्थानों पर शौचालयों तक पहुंच प्रदान करने के लिए 3095 सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सीएससी) बनाए गए हैं।

एसबीएम (जी) ने अपने चरण II में, ओडीएफ प्लस गांवों को प्राप्त करने की दृष्टि से, वित्त वर्ष 2023-24 में महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल की है। राज्य ने सभी 25437 गांवों को ओडीएफ प्लस आकांक्षी गांव घोषित किया है, जहां 4479 गांव ओडीएफ प्लस राइजिंग हैं और 999 गांव ओडीएफ प्लस मॉडल गांव हैं। इन गांवों में से 7967 गांवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है, 23466 गांवों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है और 5996 गांवों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था है। प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए, एसबीएम-जी असम ने ब्लॉक स्तर पर 88 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों का निर्माण किया है। इसके अलावा 12 बायोगैस संयंत्रों का निर्माण किया गया है जो कार्यात्मक हैं, 12 पहले से ही निर्मित हैं जो 15 जनवरी, 2024 से पहले

कार्यात्मक होंगे और 11 जिलों में गोबर धन योजना के तहत 2 संयंत्र निर्माणाधीन हैं। एसबीएम-जी असम को प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तांतरण मोड के तहत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के लिए नागरिकों से 3461287 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 189421 लाभार्थियों को मंजूरी दे दी गई है और पहली किस्त डीबीटी के तहत 106305 लाभार्थियों को हस्तांतरित कर दी गई है।

लोक निर्माण भवन और राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र -

हमारी सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सांस्कृतिक, वन्य जीवन और असम के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र: राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र के उत्थान के लिए एक प्रमुख अभियान में, लोक निर्माण (भवन और एनएच) विभाग को मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए चल रही परियोजनाओं सहित राज्य में विभिन्न स्थानों पर निर्माण गतिविधियों को शुरू करने के लिए 5500 करोड़ रुपये से अधिक का काम सौंपा गया है। धेमाजी, तिनसुकिया, चराइदेव, बिश्वनाथ, गोलाघाट, मारीगांव, तामुलपुर, बोंगाईगांव और गुवाहाटी में प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज में अस्पताल और पीएम-डेवाइन के तहत शिवसागर और करीमगंज में 2 नए आगामी मेडिकल कॉलेज। 14 अप्रैल, 2023 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा नलबाड़ी, कोकराझार और नगांव में 3 नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया जा चुका है। जेआईसीए के तहत मौजूदा 6 मेडिकल कॉलेजों में सुपर-स्पेशियलिटी विंग की स्थापना, 6 जिला अस्पतालों के बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वास्थ्य गुवाहाटी में भवन का निर्माण किया जा रहा है। मैरीगांव और लखीमपुर में 2 डेंटल कॉलेज और दीफू, जोरहाट, तेजपुर,

लखीमपुर, नागांव, नलबाड़ी, बारपेटा, कोकराझार और धुबरी में 9 नए नर्सिंग कॉलेज का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

शिक्षा क्षेत्र: राज्य में शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे कि 14 नए पॉलिटेक्निक संस्थान पूरे हो चुके हैं और हाजो, माजुली और तिंगखोंग में 3 अन्य पॉलिटेक्निक का निर्माण कार्य चल रहा है, 22 पॉलिटेक्निक संस्थानों का उन्नयन किया जा रहा है। और टाटा के सहयोग से उत्कृष्टता केंद्र के रूप में असम में 39 आईटीआई स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। चाय बागान समुदाय के बीच शिक्षा का एक नया युग लाने के लिए असम के विभिन्न चाय बागानों में 118 मॉडल हाई स्कूलों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अलावा, 100 (सौ) चाय बागान हाई स्कूलों की स्थापना, डिब्रूगढ़, जोरहाट, तिहू, लखीमपुर और तेजपुर में 5 सरकारी लॉ कॉलेज, बोंगाईगांव, बेहाली, सुआलकुची (एनआईडीए के तहत) और नागांव में 6 इंजीनियरिंग कॉलेज, नलबाड़ी, उदलगुरी (रूसा के तहत) प्रगति पर हैं। बजाली, लखीमपुर, गोलाघाट, होजाई, माजुली, जोरहाट और चबुआ में अन्य 7 विश्वविद्यालयों का काम प्रगति पर है। सिलचर में सिबसागर कॉलेज, कोकराझार सरकारी कॉलेज, बोंगाईगांव कॉलेज, जगन्नाथ बरूआ कॉलेज, नागांव कॉलेज, उत्तरी लखीमपुर कॉलेज, हांडिक गर्ल्स कॉलेज, गुरुचरण कॉलेज जैसे 8 कॉलेजों को विश्वविद्यालय स्तर पर अपग्रेड करने का काम शुरू किया गया है। राज्य में शिक्षा क्षेत्र के उन्नयन के लिए पीडब्ल्यूडी भवन विभाग को 2000.00 करोड़ रुपये से अधिक का काम सौंपा गया है।

सांस्कृतिक क्षेत्र: इस क्षेत्र के तहत, नारायणपुर में श्री श्री माधवदेव कलाक्षेत्र, जिसकी कुल परियोजना लागत 65.50 करोड़ रुपये है, का उद्घाटन 11 मई 2023 को किया गया था। बताद्रवा, नागांव में एक सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल के रूप में बताद्रवा थान का विकास जल्द ही पूरा किया जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत 191.75 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, रंग घर का सौंदर्यीकरण, मां कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर, 500 केंद्रों का निर्माण (महाप्रभु जगन्नाथ सामुदायिक हॉल सह कौशल केंद्र) कार्यान्वयन के लिए लिया गया है।

खेल क्षेत्र: राज्य में विभिन्न स्टेडियमों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण का कार्य जिसमें 15000 बैठने की क्षमता वाला खनिकर इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शामिल है, जिसकी कुल परियोजना लागत 176.64 करोड़ रुपये है, इसके अतिरिक्त, 45 मिनी-स्टेडियम और 11 जिला स्टेडियम भी शामिल हैं। 920.36 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत वाले विभिन्न स्थानों पर भी कार्य किए गए हैं।

जीएडी और अन्य: नई दिल्ली (संख्या 2), कोलकाता और बेंगलुरु में असम हाउस का काम प्रगति पर है। वेल्लोर में असम हाउस का उद्घाटन 26 सितंबर 2023 को पुरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त, 14 जिलों में एकीकृत उपायुक्त कार्यालयों के निर्माण के लिए 1000.00 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं जो वर्तमान में प्रगति पर हैं।

वन्यजीव संरक्षण: काजीरंगा, मानस और तेजपुर में तीन उपग्रह केंद्रों के साथ अत्याधुनिक वन्यजीव स्वास्थ्य और पुनर्वास सुविधा प्रदान करने के लिए दिनजान में वन्यजीव स्वास्थ्य और अनुसंधान की स्थापना, असम

राज्य चिड़ियाघर, गुवाहाटी और कछार वन्यजीव सफारी का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: 6 जिला विज्ञान केंद्र सह तारामंडल और 11 जिला विज्ञान केंद्र के निर्माण की परियोजना प्रगति पर है।

चालू/प्रस्तावित नया पुल-ब्रह्मपुत्र नदी पर काम: माजुली द्वीप को जोरहाट से जोड़ने वाले ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल का काम प्रगति पर है। एसओपीडी के तहत मिशन चरियाली, तेजपुर, एनएच-52 (नया एनएच-15) के जंक्शन बिंदु पर 4-लेन फ्लाईओवर का निर्माण प्रगति पर है, मोरीगांव-कौपति रोड पर ब्रह्मपुत्र पर प्रमुख आरसीसी पुल के लिए अंतिम व्यवहार्यता अध्ययन मंत्रालय को सौंप दिया गया है। डीपीआर की तैयारी चल रही है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क सुरक्षा मानकों का ऑडिट और रखरखाव (एसओपीडी के तहत): राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट के सुधार/हटाने के लिए किए गए सड़क सुरक्षा उपायों के फील्ड मूल्यांकन/सत्यापन और समीक्षा के लिए 30 नवंबर 2023 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के साथ एक समझौता ज्ञापन (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कार्य प्रगति पर है।

एपी 2023-24 के तहत शुरू की जाने वाली प्रमुख परियोजनाएं: गौरीपुर बाईपास, लंबाई = 9.60 किमी, लागत = 389.96 करोड़ रुपये, माजुली-जोरहाट ब्रिज पहुंच मार्ग, लंबाई = 20.479 किमी, लागत = 379.35 करोड़ रुपये, माजुली-जोरहाट ब्रिज के लिए नदी प्रशिक्षण कार्य, लागत = 245.388 करोड़ रुपये।

कौशल रोजगार एवं उद्यमिता क्षेत्र -

कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग, असम सरकार राज्य के युवाओं को कुशल बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं लागू कर रही है। हमारा लक्ष्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और प्रतिष्ठित प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से असम के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और राज्य भर में कौशल प्रयासों के अभिसरण के माध्यम से एक स्थायी कौशल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।

असम कौशल विकास मिशन में आईटीई एजुकेशन सर्विसेज (आईटीईईएस), सिंगापुर के सहयोग से "द नॉर्थ ईस्ट स्किल सेंटर" (एनईएससी) की स्थापना की गई है, जो चार विषयों में अत्याधुनिक एक साल का प्रमाणपत्र प्रशिक्षण प्रदान करता है। खाद्य और पेय सेवाएँ, आतिथ्य हाउसकीपिंग, खुदरा सेवाएँ, और सौंदर्य और कल्याण, जेडब्ल्यू मैरियट, ग्रैंड हयात, लुलु हाइपर मॉल आदि जैसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध संगठनों में सफल प्लेसमेंट के साथ एनईएससी के 17 छात्रों को बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी रखा गया है।

उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, हम सक्रिय रूप से असम कौशल विश्वविद्यालय (एएसयू) की स्थापना कर रहे हैं, जो देश के पूर्वी हिस्से में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है। एएसयू का लक्ष्य व्यावसायिक कौशल प्रयासों को नया आकार देना है, न केवल असम में बल्कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया में एक उच्च गुणवत्ता वाला कौशल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।

एएसडीएम ने गुवाहाटी हवाई अड्डे पर ड्राइवरों, होटल स्टाफ, गुरु/विशेषज्ञ के माध्यम से स्थानीय कारीगरों के काम को बढ़ावा देने, स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के कौशल को बढ़ाने, काजीरंगा में पर्यटक गाइड प्रशिक्षण के लिए अप-स्किलिंग कार्यक्रमों पर 1430 लाभार्थियों के लिए राज्य विशिष्ट विशेष परियोजनाएं शुरू की हैं। चाय जनजातियों के लिए ड्राइविंग कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट लिंक्ड कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 और 3.0 दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन राष्ट्रीय अनुसूचित जैसे अन्य विभिन्न कार्यक्रमों के अलावा अब तक कुल 539 उम्मीदवारों को सफलतापूर्वक प्रमाणित किया गया है।

नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) के तहत रोजगार के अवसरों को बढ़ाते हुए जिला रोजगार कार्यालय में सात मॉडल करियर सेंटर स्थापित किए गए हैं। Naukri.com के साथ एक समझौता ज्ञापन के कारण 4 जुलाई, 2023 को असम जॉब पोर्टल (job.assam.gov.in) का सफल लॉन्च हुआ, जिससे स्थानीय और अन्य स्तर पर नौकरी चाहने वालों के लिए अवसर उपलब्ध होंगे।

कृषि क्षेत्र –

कृषि और संबद्ध वस्तुओं को बढ़ावा देने, गुणवत्ता मानकों में सुधार करने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों का पता लगाने की सरकार की पहल के कारण असम के कृषि निर्यात बाजार में आशाजनक वृद्धि देखी गई है। हाल के वर्षों में, पारंपरिक वस्तुओं से परे निर्यात में विविधता लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें तिलहन, जूट, मसाले, चावल

(बासमती के अलावा), ताजी सब्जियां, ताजे फल, फूलों की खेती के उत्पाद, रेशम आदि शामिल हैं।

जनवरी, 2023 से अगस्त 2023 तक निर्यात में असम की हिस्सेदारी 1185 करोड़ रुपये थी, जिसकी कुल निर्यात मात्रा 49090 मीट्रिक टन थी।

असम बाजरा मिशन, राज्य में बाजरा की खेती को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार की एक नई पहल शुरू की गई थी। मिशन में बाजरा की खेती में तकनीकी सहायता के लिए अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की वैश्विक स्तर की विशेषज्ञता को शामिल किया गया। बाजरा को राज्य के पोषण कार्यक्रमों जैसे पीएम पोषण और पोषण अभियान में आपूर्ति करने की योजना है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना अपनी शुरुआत से ही देश भर के लाखों किसानों के जीवन को बदलने में सहायक रही है। पात्र किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करके; इससे उनकी वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर, 2023 को समारोहपूर्वक पीएम किसान की 15 वीं किस्त जारी की, जिससे 12.16 लाख से अधिक किसानों को सीधे लाभ हुआ, जिन्हें 487.38 करोड़ रुपये की पर्याप्त राशि प्राप्त हुई, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है। हमारा इरादा इस वर्ष सभी पात्र किसानों को पीएम किसान के दायरे में लाने का है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना - प्रति बूंद अधिक फसल के तहत, 6602 किसानों की 7,615 हेक्टेयर भूमि को कवर किया गया है, और पानी के सृजन के लिए 772 किसानों को 772 पंप सेट प्रदान किए गए हैं। स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रणाली के स्रोत। इस योजना ने राज्य के जीएसडीपी में योगदान देकर उनकी उत्पादकता में 30% की वृद्धि करके उच्च मूल्य वाले कृषि-बागवानी उत्पादकों और छोटे चाय उत्पादकों के उत्पादन में वृद्धि की है।

पशुपालन एवं पशु चिकित्सा क्षेत्र -

मेरी सरकार राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की दिशा में विभिन्न कदम उठा रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में हमारी सरकार ने लिंग क्रमबद्ध वीर्य की 1.16 लाख खुराकें खरीदीं, जिससे लगभग 50 हजार मादा बछिया पैदा होंगी। इस चालू वर्ष में भी, 363 लाख रुपये की राशि से 1.00 लाख लिंग क्रमबद्ध वीर्य की खरीद का प्रस्ताव है। यह पहल उच्च उपज देने वाली नस्लों और उत्पादक मवेशियों की मादा आबादी को बढ़ाने के लिए की गई है, जिससे राज्य में दूध उत्पादन में वृद्धि होने की उम्मीद है।

मेरी सरकार राज्य में डेयरी व्यवसाय को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक डेयरी इकाइयों की स्थापना को भी बढ़ावा दे रही है। हमारी सरकार 842 लाख रुपये के परिव्यय के साथ 17 प्रगतिशील डेयरी उद्यमियों का समर्थन करेगी। इससे राज्य में दूध उत्पादन बढ़ने और वैज्ञानिक डेयरी फार्मिंग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

चूंकि असम के किसान सीमांत डेयरी किसान हैं जो प्रतिदिन औसतन 2 बार दूध का उत्पादन करते हैं और वे भौगोलिक रूप से फैले हुए हैं, इसलिए डेयरी सहकारी समितियों जैसे मजबूत और मजबूत किसान संगठन बनाने में मदद करने की आवश्यकता है। इसे प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में 1234 लाख रुपये के परिव्यय के साथ 144 डेयरी सहकारी समितियों को बीज राशि प्रदान की गई है। इससे राज्य के लगभग 4000 सीमांत डेयरी किसानों को सीधा लाभ हुआ है।

मेरी सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में बोंगाईगांव और धेमाजी में 5000 लीटर प्रति दिन की प्रसंस्करण क्षमता के दो नए दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए हैं। दूध प्रसंस्करण संयंत्र बोंगाईगांव पहले ही चालू हो चुका है। इस वित्तीय वर्ष में हमारी सरकार दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र धेमाजी को क्रियाशील करने का इरादा रखती है।

इसके अलावा, उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) से वित्त पोषण के साथ, बजाली, बारपेटा और नलबाड़ी क्षेत्र के डेयरी किसानों द्वारा उत्पादित दूध के संगठित दूध प्रसंस्करण और विपणन के लिए पटाचारकुची, बजाली में 10000 लीटर प्रतिदिन का दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।

चालू वित्तीय वर्ष में राज्य स्व-प्राथमिकता विकास निधि (एसओपीडी-जी) के तहत चाय समुदाय के लाभार्थियों सहित 1,500 लाभार्थियों को 40-40 की दर से कुल 60,000 एक दिन के चूज़े वितरित किए गए हैं। 2,250 लाभार्थियों को 20-20 की दर से कुल 45,000 एक दिवसीय बत्तखें वितरित की गई हैं। सुअर विकास के क्षेत्र में रु. चालू

वित्तीय वर्ष में निजी क्षेत्र के सुअर पालन के लिए 6 करोड़ 30 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं. इसके अलावा, अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से चालू वित्तीय वर्ष के लिए 4 करोड़ 63 लाख 50 हजार (463.50 लाख) आवंटित किए गए हैं।

पशु चिकित्सा सेवाओं में तेजी लाने के उद्देश्य से पशुपालकों के घर-घर जाकर उनके पशुओं के इलाज और उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए 181 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। अब हमारे पशुपालक "1962" पर कॉल करके अपने घर में ही इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) ने सूअरों और बकरियों के कृत्रिम गर्भाधान के लिए शहर के खानापारा में एक सुअर और बकरी वीर्य केंद्र स्थापित किया है। इसके अलावा, अंडे और मांस का उत्पादन बढ़ाने के लिए लाभार्थियों के बीच 72,800 लेयर्स, 120,000 ब्रॉयलर चूजों और 2,680 बकरियों को वितरित किया गया है। इसके अलावा, पशुधन के लिए हरी घास की मांग को पूरा करने के लिए संकर चारे की खेती के लिए 5,400 लाभार्थियों में से प्रत्येक को 4,000/- रुपये प्रति बीघे दिए जाएंगे। इसी तरह, किसानों के बीच मोरिंगा की खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट पर 9.9 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

असम कृषि, व्यापार और ग्रामीण परिवर्तन योजना (एपीएआरटी) द्वारा सूअरों के कृत्रिम गर्भाधान के लिए खानापारा, जोरहाट और सिबसागर में तीन सुअर वीर्य केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

मांस उत्पादों, फलों, सब्जियों आदि को विभिन्न तापमानों पर संग्रहीत करने के लिए असम पशुधन और पोल्ट्री निगम के परिसर में 1000 मीट्रिक टन की क्षमता वाला एक "कोल्ड स्टोरेज" बनाया गया है।

गांठदार त्वचा रोग, पीपीआर, एफएमडी और ब्रुसेलोसिस के उन्मूलन के लिए पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग चरणबद्ध तरीके से पशुओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चला रहा है। इसी प्रकार विभाग की ओर से पालतू पशुओं को रेबीज टीकाकरण कार्यक्रम भी चल रहा है।

प्रशासनिक सुधार, प्रशिक्षण, पेंशन और लोक शिकायतें -

शासन में अधिक दक्षता और पारदर्शिता लाने और सरकार को जनता के दरवाजे तक लाने के लिए, ARTPPG विभाग ने विभिन्न पहल की हैं। सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए, असम नागरिक केंद्रित सेवा वितरण परियोजना के तहत असम राइट टू पब्लिक सर्विस (ARTPS) पोर्टल की तर्ज पर सेवा सेतु पोर्टल पेश किया गया है। इसकी स्थापना के बाद से विभिन्न विभागों और स्वायत्त परिषदों की 541 महत्वपूर्ण सेवाएँ शामिल हैं। 11.01.2024 तक, इस पोर्टल पर 1,10,12,006 आवेदन प्राप्त हुए हैं और जिनमें से 71.73% से अधिक प्रसंस्करण दर के साथ 77,55,249 आवेदनों का निपटान किया जा चुका है।

सेवा सेतु के तहत, शिकायत निवारण प्रबंधन (जीआरएम) एप्लिकेशन को केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के साथ एकीकृत किया गया है। असम लगातार उत्तर-पूर्वी राज्यों में तीन शीर्ष स्थानों पर रहा और निपटान के मामले में भी देश भर में अग्रणी स्थान पर रहा और इसलिए सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए राज्य के रूप में प्रदर्शित हुआ।

मिशन सद्भावना 2.0, सभी उपायुक्त कार्यालयों के साथ-साथ सरकार के निदेशालयों और आयुक्तालयों में लागू किया जा रहा है। असम की, पुरानी लंबित फाइलों/मामलों को एक निर्धारित समय के भीतर निपटाने और फ़ाइल वर्गीकरण और ई-ऑफिस के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। 11 जनवरी 2024 तक पोर्टल पर 157 आवेदन प्राप्त हुए तथा 58 आवेदनों का निस्तारण किया गया।

कृतज्ञता पोर्टल के उपलब्ध संस्करण में पेंशनभोगियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए, जो सेवानिवृत्ति प्रक्रियाओं पर सभी आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करता है, अनुकंपा पारिवारिक पेंशन (सीएफपी) (सेवाकालीन मृत्यु) और अनंतिम पेंशन और अनंतिम डीसीआरजी को इसमें पेश किया गया है। कृतज्ञता 2.0 पोर्टल। 10 जनवरी, 2024 तक, कृतज्ञता पोर्टल के तहत 59 विभाग पंजीकृत हो चुके हैं और 19197 पीपीओ जारी किए जा चुके हैं।

इसके अलावा, ARTPPG विभाग के तहत सरकारी नियमों/मैनुअल/अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए हैं। (ए) पेंशन की पुस्तिका, पेंशन मामलों से संबंधित विभिन्न अधिसूचनाओं, कार्यालय ज्ञापनों का एक संग्रह तैयार किया गया है। (बी) असम कार्यकारी व्यवसाय नियम, 1968 का संशोधन व्यापक तरीके से संशोधित किया गया है और 1 सितंबर, 2023 को असम कार्यकारी व्यवसाय नियम, 2023 के रूप में अधिसूचित किया गया है। (सी) असम सेवाओं के नियम 13, 15 और फॉर्म 3 भाग II का संशोधन (पेंशन का कम्युटेशन) नियम, 1965। सद्भावना पोर्टल में एक नई सुविधा भी विशेष रूप से पेंशन

संबंधी सभी शिकायतों को स्वीकार करने और निपटाने के लिए सौंपी गई है। कृतज्ञता पोर्टल के माध्यम से पेंशन प्रस्ताव अग्रेषित करने के लिए कार्यालय प्रमुख की शक्तियों का अगले वरिष्ठ अधिकारी को प्रत्यायोजन किया गया है।

जीवन प्रमाण पत्र के लिए स्वयं को उपस्थित हुए बिना पेंशनभोगियों के लिए आसानी से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए, जीवन प्रमाण पोर्टल शुरू किया गया है, जहां 11 जनवरी 2024 तक पंजीकृत पेंशनभोगियों की कुल संख्या 10123 है।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, आरटीआई पोर्टल 2024 में लॉन्च किया जाएगा। असम सूचना आयोग (एआईसी) में सुनवाई का 1 लाइब्रिड मोड, आरटीआई मामलों का ऑनलाइन पंजीकरण, ऑनलाइन कॉज-लिस्ट आदि 2020 से काम कर रहे हैं।

सीमा सुरक्षा एवं विकास -

पहली साहसिक और सकारात्मक पहल मेघालय राज्य के साथ की गई है। जिसमें अंतर के पहले छह क्षेत्रों यानी तारावारी, गिज़ांग, हाहिम, बोक्लापारा, खानापारा-पिलंगकाटा और रातचेर्रा के संबंध में जटिल सीमा मुद्दों को हल करने के लिए एक अग्रणी पहल अपनाई गई थी। 5 सिद्धांतों - 1) प्रशासनिक सुविधा, 2) निकटता, 3) जातीयता, 4) लोगों की राय और 5) ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का उपयोग करके स्थानीय लोगों और सामुदायिक संगठन के साथ जुड़ने के लिए दोनों पक्षों के मंत्रियों की अध्यक्षता में 3 क्षेत्रीय समितियों की स्थापना की गई। इन

समितिओं पर आधारित सिफारिशों पर केंद्रीय गृह मंत्री, सरकार की उपस्थिति में असम और मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मेघालय के साथ मतभेद के छह क्षेत्रों में इस अनूठी पहल को सफल बनाने के लिए 29 मार्च 2022 को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री, भारत सरकार की उपस्थिति में असम और मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

अरुणाचल प्रदेश के साथ भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। 20 अप्रैल 2023 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन ने 123 दावा किए गए गांवों में से 71 पर मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया और सीमाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। शेष गांवों को उचित समय सीमा के भीतर।

पर्यावरण एवं वन क्षेत्र -

राज्य के वनों, जंगली जानवरों और जैव विविधता की रक्षा, संरक्षण के लिए, अमृत वृक्ष आंदोलन, 2023 नामक एक मेगा वृक्षारोपण अभियान 17 सितंबर, 2023 को चलाया गया था, जिसमें व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य पेड़ों की 53 प्रजातियों के एक करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए थे। जनभागीदारी मॉडल के माध्यम से जिसमें एसएचजी के सदस्यों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, वीडीपी सदस्यों, चाय बागानों, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी विभागों को शामिल किया गया है। अमृत वृक्ष आंदोलन, 2023 के कार्यान्वयन के दौरान 10 (दस) संख्या में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए।

इसके अलावा, 2023-24 के दौरान 3951.58 हेक्टेयर (29,636 बीघा) वन भूमि पर कुल 89,73,950 पौधे लगाए गए हैं। साथ ही, अमृत वृक्ष आंदोलन, 2024 के तहत वृक्षारोपण के लिए राज्य भर में 54 (चौवन) नर्सरियों में 4 (चार) करोड़ पौधे उगाए जा रहे हैं, जिसके लिए 2024-25 के दौरान ₹160.57 करोड़ निर्धारित किए जा रहे हैं।

जानवरों, पौधों के वर्तमान और ऐतिहासिक रिकॉर्ड प्रदर्शित करने और असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता विरासत को प्रदर्शित करने के लिए गोलाघाट जिले के बोरजुली, पनबारी में एक प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय और पशु बचाव केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। परियोजना को निष्पादित करने के लिए आवश्यक कुल बजट 700 करोड़ रुपये है।

असम राज्य में वन्यजीव स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान बुनियादी ढांचे और परीक्षण सुविधा को मजबूत करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक होकर, सरकार ने डिब्रूगढ़ के दिनजान में 'वन्यजीव स्वास्थ्य और अनुसंधान संस्थान (आईडब्ल्यूएच एंड आर)' की स्थापना पर तेजी से काम किया है और 94 बीघा भूमि आवंटित की है। इसी तरह, असम राज्य चिड़ियाघर का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण कुल 311.75 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा और 2024-25 के लिए निर्धारित फंड 32 करोड़ रुपये होगा। साथ ही, कछार जिले के धोलाई में बराक वैली वाइल्डलाइफ सफारी और रेस्क्यू सेंटर के निर्माण के लिए 214.54 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, डिब्रूगढ़ में

नए वन्यजीव सफारी और बचाव केंद्र को सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जा रही है।

एपीएफबीसी की बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना के तहत, फ्रंटलाइन वन कर्मचारियों / अवैध शिकार विरोधी शिविरों के लिए 108 भवनों का निर्माण किया गया है, 858 वन सीमांत समुदायों के सदस्यों को 18 वैकल्पिक आजीविका व्यवसायों में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा, 50 पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (पीबीआर) को अद्यतन किया गया है और 1556 हेक्टेयर वृक्षारोपण किया गया है और परियोजना के तहत 'असम की दुर्लभ और संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियों' पर एक पुस्तिका प्रकाशित की गई है।

संरक्षण और आवास प्रबंधन प्रयासों को मजबूत करने के लिए, वर्ष 2023 के दौरान लोखोवा बुराचापोरी वन्यजीव अभयारण्य, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व और गोलपारा डिवीजन में कुल 5179 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। अवैध शिकार विरोधी गतिविधियों में दक्षता बढ़ाने के लिए अग्रिम पंक्ति के वन कर्मचारियों के लिए आधुनिक हथियारों और गोला-बारूद की खरीद के लिए 18.00 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।

प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत, व्हाइट विंग वुड डक को स्थानीय रूप से देव हान (असम का राज्य पक्षी), हूलॉक गिब्बन, और कुछ स्थानिक और लुप्तप्राय वनस्पतियों जैसे होलोंग (असम का राज्य वृक्ष), मेकाई, बोन्सम, अमारी, बोला और गुर्जन के रूप में जाना जाता है। ऐसी पहचान की गई है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। 10 वर्षों की

अवधि के लिए 150 करोड़ रुपये की राशि और 2024-25 के बजट में 15 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन को कम करने के लिए, असम सरकार ने असम में 500 मिलीलीटर से कम की पीईटी पीने के पानी की बोतलों के निर्माण, बिक्री, उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो इस तरह का प्रतिबंध लगाने वाला देश का अग्रणी राज्य है।

राज्य में जैव चिकित्सा अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए, डिब्रूगढ़ में तीसरी सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा (सीबीडब्ल्यूटीएफ) स्थापित की जा रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम ने तेजपुर, सिलचर और जोरहाट में भी ऐसी सुविधाएं स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) असम के गुवाहाटी, नागांव, नलबाड़ी, सिलचर और शिवसागर शहर में लागू किया गया है। हाल के एक सर्वेक्षण में, शिवसागर को देश में सबसे कम प्रदूषित एनसीएपी शहर के रूप में पहचाना गया है। एनसीएपी की कार्रवाई के बाद, राज्य के लिए राज्य स्वच्छ वायु कार्यक्रम तैयार किया गया है।

उत्पाद शुल्क क्षेत्र -

राज्य के राजस्व संग्रह को बढ़ाने के लिए, उत्पाद शुल्क विभाग कड़ी मेहनत कर रहा है और मेरी सरकार ने राज्य में अवैध और नकली शराब की बिक्री और खपत को रोकने, स्वास्थ्य संबंधी खतरों को रोकने

और शराब व्यवसाय में सुरक्षा मानक बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं।

उपभोक्ताओं को अवैध शराब का सेवन करने से रोकने के लिए, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती है, उत्पाद शुल्क विभाग ने शराब की बोतलों पर क्यूआर कोड के साथ छेड़छाड़ मुक्त उच्च सुरक्षा होलोग्राम पेश किए हैं और तस्करी की शराब की बिक्री के माध्यम से चोरी पर भी अंकुश लगाया है। विभाग ने पड़ोसी राज्यों से अवैध शराब की आमद को रोकने के लिए शराब की खेप के परिवहन में ट्रांजिट पास प्रणाली भी शुरू की है। प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में आबकारी राजस्व में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चालू वित्तीय वर्ष, 2023-24 के दौरान, उत्पाद शुल्क विभाग रुपये का राजस्व एकत्र करने में सक्षम रहा है। 31 दिसंबर, 2023 तक वैट सहित 3371.07 करोड़ रुपये। वर्ष 2023-24 के दौरान उत्पाद शुल्क राजस्व, लागू वैट सहित 3000 करोड़ रुपये के संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वित्त क्षेत्र –

वित्त क्षेत्र के संबंध में, मेरी सरकार ने निम्नलिखित पहल की हैं -

सरकार ने पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन के लिए समर्पित संसाधनों की पहचान करने, उन्हें सुव्यवस्थित करने और आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप के कार्यान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से हरित बजट और लचीलापन बजट पेश किया है। हमने वित्त वर्ष 22-23 में बजटीय व्यय 1.20 लाख करोड़ रुपये को पार कर लिया है, अर्थव्यवस्था 5 लाख करोड़ रुपये के जीएसडीपी को पार कर गई है।

ORUNODOI 2.0 योजना इस वर्ष सफलतापूर्वक शुरू की गई है, जिसमें राज्य की अंत्योदय महिलाओं के साथ-साथ ट्रांसजेंडर, दिव्यांगजन और दीन दयाल दिव्यांगजन पेंशन योजना और इंदिरा मिरी यूनिवर्सल विधवा पेंशन योजना के मौजूदा लाभार्थियों को भी समग्र सामाजिक-आर्थिक के लिए इस दायरे में लाया गया है। महिलाओं का विकास एवं आर्थिक सशक्तिकरण। आज, सरकार इस योजना के माध्यम से हर महीने 25 लाख ओरुनोडोई परिवारों को सहायता प्रदान कर रही है।

असम माइक्रो फाइनेंस प्रोत्साहन और राहत योजना (एएमएफआईआरएस), 2021 उन उधारकर्ताओं को प्रोत्साहन और राहत देने के उद्देश्य से तैयार की गई थी, जिन्होंने असम राज्य में विभिन्न माइक्रोफाइनेंस ऋण संस्थानों से छोटे ऋण प्राप्त किए थे। अब तक लगभग 12 लाख सूक्ष्म उधारकर्ताओं को 2000 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय वाली योजना के तहत लाभ दिया गया है।

वित्त विभाग ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को सस्ता गृह ऋण प्रदान करने के लिए अपोन घर, राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा मोटर वाहनों की खरीद के लिए ब्याज छूट प्रदान करने के लिए अपुन घर, असम और असम चाय उद्योग विशेष के बच्चों द्वारा उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी प्रदान करने के लिए अभिनंदन को भी लागू किया है। प्रोत्साहन योजना (एटीएसआईएस) चाय निर्माताओं को सब्सिडी प्रदान करके पारंपरिक और अन्य विशेष चाय के उत्पादन पर प्रोत्साहित करने के लिए है।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, नवंबर, 2023 तक, कर विभाग पिछले वर्ष 2022-23 की समान अवधि की तुलना में 14% की वृद्धि दर के साथ 16430 करोड़ रुपये एकत्र करने में सक्षम रहा है।

चाय उद्योगों को कुछ राहत देने के लिए, "कृषि आयकर अधिनियम" के तहत छूट को 1 अप्रैल, 2023 से तीन साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

व्यापार और उद्योगों द्वारा हरित और स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए, हरित ऊर्जा के उपयोगकर्ताओं को 1 अप्रैल, 2023 से तीन साल की अवधि के लिए बिजली की खपत के लिए नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पादन पर बिजली शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

सुधार एजेंडा

असम ने असम सार्वजनिक खरीद अधिनियम 2017 और असम खरीद नियम, 2020 लागू किया है। उल्लेखनीय रूप से, असम में GeM ने अन्य राज्यों को पीछे छोड़ते हुए लेनदेन की मात्रा में 504% की असाधारण वृद्धि दर देखी है।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (एफएमआईएस) के कार्यान्वयन से व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्रचना के माध्यम से अनावश्यक प्रक्रियाओं में कमी आई है। विभाग ने राज्य भर में ऑनलाइन वेतन बिलों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र लागू किया है, इस संबंध में राज्य भर के सभी संवितरण और आहरण अधिकारियों को लगभग 10000 डीएससी प्रदान किए गए हैं।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्लेटफॉर्म- डीबीटी स्कीम्स (डीआईडीएस) के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त विभाग द्वारा सब्सिडी और अन्य लाभों को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित करने के लिए लॉन्च किया गया है। वर्तमान में कई डीआईडीएस योजनाएं शुरू की गई हैं यानी ओरुनोडोई, एटीआईटीएस।

सामान्य प्रशासन क्षेत्र -

मेरी सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के अनुसरण में, असम भवन, वेल्लोर का उद्घाटन 26 सितंबर, 2023 को किया गया। 40 से अधिक कमरों वाला जी+6 मंजिल भवन पूरी तरह कार्यात्मक हो गया है और असम आने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। वेल्लोर मुख्य रूप से चिकित्सा और अन्य संबद्ध उद्देश्यों के लिए।

असम भवन, बेंगलुरु का निर्माण भी तेजी से चल रहा है और 2024 में पूरा हो जाएगा।

प्रशासनिक समीचीनता के लिए, जमीनी स्तर पर अधिकतम तालमेल, उत्पादकता और दक्षता प्राप्त करने के लिए और एक अच्छे नागरिक-केंद्रित प्रशासन की सहायता के लिए, 78 (अहत्तर) उप जिले बनाए गए हैं। उप-जिलों की भौगोलिक सीमाएँ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के साथ समाप्त होंगी।

सेक्टर-17 द्वारका में एक अतिरिक्त गेस्ट हाउस / भवन और सांस्कृतिक परिसर के निर्माण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से 4000 वर्ग मीटर की भूमि का एक नया भूखंड खरीदा गया है।

असम सरकार के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए वर्ष 2022 में लोक सेवा पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। वर्ष 2023 में, राज्य स्तर पर 10 को और जिला स्तर पर 65 को यह पुरस्कार दिया गया।

गृह एवं राजनीतिक विभाग –

हमारी सरकार ने एआईएसएफ के कर्मियों को औद्योगिक सुरक्षा पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए असम के गुवाहाटी के पानीखैती में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के परिसर में राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी, हैदराबाद की तर्ज पर राज्य औद्योगिक सुरक्षा अकादमी, असम की स्थापना को अधिसूचित किया।

सुरक्षा मॉड्यूल को कड़ा करने और असम की जेलों में प्रतिबंधित वस्तुओं की अवैध तस्करी को रोकने के लिए 04/12/2023 तक 25 जेलों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना पूरी हो चुकी है। शेष 06 जेलों में स्थापना के उपाय प्रक्रियाधीन हैं।

शहर के केंद्र में स्थित मौजूदा जेलों को बाहरी इलाकों में स्थानांतरित करने के उद्देश्य से तेजपुर, गोलपारा, शिवसागर, मंगलदोई, लखीमपुर और धुबरी में भूमि आवंटित की गई है और जेल अधिकारियों को सौंप दी गई है। नए स्थानों पर उपरोक्त जेलों के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की प्रक्रिया पीडब्ल्यूडी को सौंपी गई है और प्रक्रियाधीन है।

चिरांग, बक्सा और नारायणपुर, हैलाकांडी (चरण-द्वितीय) में 3(तीन) नई जिला जेल का निर्माण चल रहा है। जिला जेल, चिरांग और बक्सा का संकुचन चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूरा होने की संभावना है।

केंद्रीय जेलों, गुवाहाटी, तेजपुर, जिला जेलों, मोरीगांव, अभयपुरी, कोकराझार, माजुली, धेमाजी और मंगलदोई में गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन के अनुसार ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग सेल के निर्माण को असम सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है।

इस वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्रीय जेलों, गुवाहाटी और तेजपुर, जिला जेलों, कोकराझार, अभयपुरी, बिस्वंथ चरियाली, बारपेटा और धेमाजी में 05 (पांच) बिस्तर वाले महिला अस्पताल के निर्माण को असम सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की पहल के तहत कामरूप में 255 कैदियों के लिए एक उच्च सुरक्षा जेल की स्थापना निविदा प्रक्रिया के तहत है। भारत सरकार पहले चरण के लिए 10.00 करोड़ रुपये की राशि पहले ही प्रदान कर चुकी है।

वर्ष 2023 के लिए "करागर प्रेरोना बोटा 2023" को जेल विभाग की बेहतरी के लिए उनकी समर्पित सेवा और योगदान के लिए 06 नामांकित जेल सुरक्षा कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।

आवास एवं शहरी क्षेत्र –

शहरीकरण का विकास की राह पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शहरी क्षेत्रों में, बुनियादी ढांचे का विकास इसके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। मेरी सरकार ने राज्य के शहरी क्षेत्रों को जनता के लिए पूरी तरह से किफायती बनाने के लिए विभिन्न पहल की हैं।

वर्तमान में JICA सहायता प्राप्त जल आपूर्ति परियोजना के तहत 25 डीएमए में 16,844 घरों को नियमित रूप से पानी की आपूर्ति की जा रही है और सभी क्षेत्रों को जून 2024 तक कवर किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम गुवाहाटी जल आपूर्ति परियोजना भी 2 साल के भीतर पूरी हो जाएगी। इसके अलावा, न्यू डेवलपमेंट बैंक की 882.67 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से दक्षिण-पूर्व गुवाहाटी जल आपूर्ति परियोजना से गुवाहाटी शहर के दक्षिण-पूर्व क्षेत्र के 67,000 परिवारों को लाभ होगा। इससे गुवाहाटी शहर का 100 फीसदी हिस्सा कवर हो जाएगा।

नगांव, सिलचर और डिब्रूगढ़ में AMRUT मिशन की जल आपूर्ति परियोजनाओं के तहत, 49,815 घरों को पानी उपलब्ध कराने का काम पूरा होने वाला है। AMRUT 2.0 के तहत 970 करोड़ रुपये में 23 और शहरों को लिया जा रहा है।

31 जुलाई 2023 को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा 1250 करोड़ रुपये के पीपीआर को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना के तहत बारपेटा, नलबाड़ी, धुबरी, गोलपारा, बोंगाईगांव और गोलाघाट में 6 (छह) जल आपूर्ति योजनाएं, गुवाहाटी शहर में एक तूफान जल निकासी प्रणाली और अन्य शहरी सुधार घटकों को एशियाई विकास बैंक की वित्तीय सहायता से शुरू करने का प्रस्ताव है। एडीबी)। यह परियोजना आवास और शहरी मामलों के विभाग यानी असम शहरी बुनियादी ढांचा विकास और वित्त निगम लिमिटेड (एयूआईडीएफसीएल) के तहत एक नव निर्मित कंपनी द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।

गुवाहाटी स्मार्ट सिटी लिमिटेड लगभग 2000 स्थापित करने जा रहा है। "गुवाहाटी शहर में इंटेलिजेंट सिटी सर्विलांस" परियोजना के माध्यम से सीसीटीवी कैमरे, जिसके लिए मामला प्रक्रियाधीन है।

स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत "गुवाहाटी में लेन और बायलेन में नियंत्रण पैनल के साथ स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम की स्थापना" का कार्य भी प्रगति पर है।

स्मार्ट मोबिलिटी और ग्रीन ट्रांसपोर्ट पहल के तहत, गुवाहाटी स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने एएसटीसी के लिए 100 सीएनजी बसें और 200 एसी ईवी बसें खरीदी हैं जो अब गुवाहाटी की सड़कों पर चल रही हैं, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो गया है। गुवाहाटी शहर 2025 तक 100% हरित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली द्वारा संचालित होने वाले पहले शहरों में से एक है।

प्रधान मंत्री आवास योजना "सभी के लिए आवास" के तहत किफायती आवास के लिए शहरी एक प्रमुख मिशन है, जिसमें कुल 87,996 पीएमएवाई-यू बीएलसी घर पूरे हो गए हैं और लाभार्थियों ने घरों में रहना शुरू कर दिया है। इसके अलावा, पीएमएवाई एचएफए (शहरी), असम के लाभार्थी नेतृत्व निर्माण (बीएलसी) घटक के तहत लाभार्थी नेतृत्व निर्माण (बीएलसी) घटक के तहत 1,72,552 घरों को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

कचरा मुक्त स्थिति प्राप्त करने की दृष्टि से, विभाग ने पहले ही कुल परियोजना के साथ राज्य के यूएलबी में सभी आधुनिक सुविधाओं के

साथ 34 आकांक्षी शौचालय ब्लॉकों और समान डिजाइन के 118 सामान्य सार्वजनिक शौचालय ब्लॉकों का निर्माण शुरू कर दिया है। 15.72 करोड़ रुपये की लागत, (ii) 123.79 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ यूएलबी में गीले अपशिष्ट खाद संयंत्रों, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं और सेनेटरी लैंडफिल साइटों की स्थापना और (iii) 12 (बारह) सीवेज की स्थापना उपचार संयंत्र सह मल कीचड़ उपचार संयंत्र (एसटीपी सह एफएसटीपी) जिसकी कुल परियोजना लागत 207.15 करोड़ रुपये है।

ब्लू-ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए तथा शहरी हरित आवरण और प्राकृतिक जल प्रणालियों को संरक्षित करने के लिए विभिन्न पहल की गई हैं। इसी उद्देश्य से गुवाहाटी में कई नए पार्कों को विकसित किए गए। जैसे (i) उज़ानबाजार में 'जोरपुखुरी पार्क', (ii) पानबाजार में 'नेहरू पार्क' आदि। हाल ही में फैंसी बाजार में 'बॉटनिकल गार्डन' का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा, आगामी वर्ष में 10 (दस) अतिरिक्त पार्क विकसित किए जाएंगे। इसी तरह, राज्य के विभिन्न जिलों जैसे गोलाघाट, तिनसुकिया, तेजपुर आदि में कई पार्क विकसित किए जा रहे हैं।

सरकार ने एकमात्र रामसर साइट दीपोर बील की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विभिन्न पहल की हैं, जैसे कि पूर्ण जल प्रसार का विस्तार, एक परिधीय सड़क का विकास, सीमांत क्षेत्र के आसपास कोई विकास गतिविधियों की अधिसूचना, शहर के सीवर का डायवर्जन, उचित स्लुइस गेट और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, साइकिल ट्रैक, व्यू प्वाइंट आदि की स्थापना। इसी तरह, हमारे कृत्रिम बाढ़ के मुद्दों के समाधान के

लिए स्पंज सिटी अवधारणा के अनुरूप सिलसाकू वेटलैंड का कायाकल्प पहले ही शुरू किया गया है।

नगर पालिकाओं को मजबूत करने और सुचारू कामकाज के लिए, एकीकृत पोर्टल बनाया गया है जहां सभी सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया गया है। इससे नागरिक केंद्रित सेवाओं का लाभ उठाना आसान हो गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों में असम में सबसे अधिक सुवितरित शहरी आबादी है। लेकिन 25% से अधिक शहरी आबादी गुवाहाटी में केंद्रित है। शहरी समूह को विनियमित करने और राज्य के समग्र शहरी विकास के लिए व्यापक और नियोजित विकास लाने के लिए एक ठोस प्रयास, "10 शहर विकास अवधारणा (दस शहर - एक रूपायन)" का प्रस्ताव शुरू किया गया है। इस पहल में राज्य की 50000 से 100000 के बीच आबादी वाले 10 शहरों अर्थात् तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, सिबसागर, जोरहाट, गोलाघाट, नागांव, तेजपुर, उत्तरी-लखीमपुर, बोंगाईगांव, सिलचर, करीमगंज और धुबरी को अन्य छोटे यूएलबी के लिए लाइट हाउस के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। इस अवधारणा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ और पीने योग्य जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, यातायात प्रबंधन, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसे टाउन हॉल, कन्वेंशन सेंटर, बाजार आदि जैसे विभिन्न घटक शामिल होंगे।

असम समझौता क्षेत्र -

असम समझौते के त्वरित और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मेरी सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं -

वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार द्वारा असम आंदोलन पीड़ित कल्याण ट्रस्ट को 5 करोड़ रुपये और सरकार द्वारा ट्रस्ट को 2.5 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में. उपरोक्त राशि (37 लाख रुपये) की सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज का उपयोग किया जाएगा -

क) पीड़ित परिवारों के बच्चों की उच्च शिक्षा,

ख) पीड़ित परिवारों के परिवार के सदस्यों का चिकित्सा उपचार,

ग) पीड़ित परिवारों की अविवाहित लड़कियों का विवाह,

घ) पीड़ित परिवारों के बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता।

वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में असम आंदोलन के पीड़ित परिवारों को अनुग्रह अनुदान के रूप में 720 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। पीड़ित परिवारों को भुगतान की प्रक्रिया चल रही है।

असम आंदोलन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की तैयारी के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में 50.00 लाख रुपये रखे गए हैं।

असम समझौते के कार्यान्वयन विभाग ने 10 दिसंबर 2023 को स्वाहिद दिवस के दौरान 380 जिला पुस्तकालयों, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों, उप-विभागीय पुस्तकालयों और सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज पुस्तकालयों को असम आंदोलन के इतिहास और घटनाओं पर डेटा पुस्तकों का एक सेट वितरित किया है।

स्वदेशी और जनजातीय आस्था और संस्कृति -

स्वदेशी और जनजातीय आस्था और संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और संरक्षण के जनादेश को साकार करने के लिए, मेरी सरकार ने निम्नलिखित योजनाएं लागू की हैं और 2024 के दौरान प्राथमिकता योजना शुरू करने का भी प्रस्ताव है।

स्वदेशी और जनजातीय आस्था और संस्कृति निदेशालय

16 जुलाई, 2023 को 18 स्वदेशी और जनजातीय आस्था और संस्कृति संगठनों और 73 (तहत्तर) स्वदेशी और जनजातीय आस्था और संस्कृति के पूजा स्थलों को 545.00 लाख रुपये की अनुदान सहायता वितरित की गई है। आगे अनुदान-16 जुलाई, 2023 को दुलाराई बाथौ गौथुम (सभी बाथौ महासभा) को 200.00 लाख रुपये की सहायता भी प्रदान की गई। माननीय मुख्यमंत्री ने उस दिन व्यक्तिगत रूप से लाभार्थियों को चेक वितरित किए है।

हाल ही में सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए कालीचरण ब्रह्मा सेवाश्रम, भैरबकुंडा को 15.00 लाख रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की गई है।

2024 के दौरान शुरू की जाने वाली प्रस्तावित प्राथमिकता योजनाएँ इस प्रकार हैं:-

संग्रहालय निदेशालय

संग्रहालय संग्रह, संरक्षण, दस्तावेज़ीकरण, प्रदर्शन और शिक्षा के माध्यम से मूर्त सांस्कृतिक वस्तुओं के संरक्षण के लिए संस्थानों के रूप में कार्य करते हैं। संग्रहालय निदेशालय 84 साल पुराने असम राज्य संग्रहालय और असम के विभिन्न जिलों में फैले 10 (दस) अन्य संग्रहालयों

का प्रबंधन करता है। संग्रहालय को जनता के करीब लाने के लिए, विशेष रूप से युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए, पांडुलिपि पेंटिंग, शोलापिथ कला और संरक्षण पर कार्यशालाएं जैसे कई शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। स्वर्गीय डॉ. राबिन देव चौधरी की स्मृति में अकादमिक व्याख्यान और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के उपलक्ष्य में सेमिनार भी सफलतापूर्वक संपन्न हुए।

पथरुघाट स्मारक संग्रहालय (चरण I) पूरा होने वाला है, जबकि दखिनपत सत्रा, माजुली में संग्रहालय के निर्माण का काम भी अच्छी प्रगति पर है। बरपेटा में जिला संग्रहालय के भवन के निर्माण के लिए स्थल विकास कार्य बहुत जल्द पूरा किया जाएगा और सिलचर में जिला संग्रहालय के निर्माण के लिए एक नई बड़ी साइट की पहचान की गई है।

इसके अलावा, जोरहाट में स्वर्गदेव चाओलुंग सिउ-का-फा समनवे क्षेत्र में असम राज्य संग्रहालय का दूसरा परिसर प्रस्तावित है। इस बीच असम राज्य संग्रहालय में कनक लाल बरुआ सभागार का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है। जिला संग्रहालय मंगलदै में गैलरी विकास कार्य भी शुरू किया गया है।

पुरातत्व निदेशालय:

पुरातत्व निदेशालय, असम ने अपना कैलेंडर कार्यक्रम, 'विश्व विरासत सप्ताह-2023' 19 से 25 नवंबर, 2023 तक चराइदेव मैदाम पुरातत्व स्थल, चराइदेव जिला, आरएम नाथ पुरातत्व पार्क, होजई जिले में और पुरातत्व निदेशालय, असम, गुवाहाटी में आयोजित किया।

पुरातत्व निदेशालय, असम ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की अंतिम सूची में शामिल करने के लिए यूनेस्को को 'मोइदम्स - अहोम राजवंश की टीला-दफन प्रणाली' पर यूनेस्को विश्व धरोहर ड्राफ्ट नामांकन डोजियर प्रस्तुत किया। ICOMOS विशेषज्ञ, श्री लिम चेन सियान ने साइट के मूल्यांकन के लिए 7 से 11 अक्टूबर, 2023 तक चराइदेव मैदाम्स पुरातत्व स्थल का दौरा किया। 24 नवंबर, 2023 को पेरिस में विश्व धरोहर मूल्यांकन पैनल की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और असम सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

पुरातत्व निदेशालय, असम ने अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 में अन्वेषण, उत्खनन, संरक्षण और विकासात्मक कार्यों के लिए निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं/स्थलों का प्रस्ताव दिया है:

ए) बदरपुर किला पुरातत्व स्थल, बदरपुर, करीमगंज जिला

बी) चराइदेव पुरातत्व स्थल, सुकाफा नगर, चराइदेव जिला

सी) जागरूकता कार्यक्रम (पुरालेख कार्यशाला)

डी) सांस्कृतिक संपत्तियों के संरक्षण में छात्रों की भागीदारी।

ई) बराक घाटी और कोकराझार जिले में अन्वेषण।

एफ) गुप्तेश्वर देवालय, डेकियाजुली, सोनितपुर जिले में उत्खनन।

जी) दीमा हसाओ जिले में स्टोन-जार साइटों का सर्वेक्षण और दस्तावेज़ीकरण।

एस) देवपर्वत पुरातत्व स्थल, नुमालीगढ़, गोलाघाट जिले का रखरखाव और विकास।

प्रमुख चल रही विकासात्मक योजनाएँ-

a) रुद्रेश्वर देवालय पुरातत्व स्थल, उत्तर-गुवाहाटी, कामरूप जिला

बी) कामाख्या मंदिर, सिलघाट, नागांव जिला

ग) नृसिंह देवालय पुरातत्व स्थल, जखलाबंधा, नागांव जिला।

घ) चराइदेव मोइदम्स पुरातात्विक स्थल, सुकाफा नगर, चराइदेव जिला का बुनियादी ढांचा, संरक्षण, संरक्षण।

ऐतिहासिक और पुरातन अध्ययन निदेशालय:

एक नई पुस्तक "ताई अहोम ग्रामर" प्रकाशित की और "लचित बरफुकन और उनके समय" सहित 9 (नौ) पुरानी और दुर्लभ पुस्तकों का पुनर्मुद्रण किया। 6 से 8 अप्रैल, 2023 को काजीरंगा में आयोजित "गज उत्सव" में भाग लिया और दुर्लभ पांडुलिपियों का प्रदर्शन किया। गुवाहाटी, शिवसागर और नलबाड़ी में आयोजित विभागीय प्रकाशनों की बिक्री के लिए असोम ग्रंथ मेले में भी भाग लिया। इस निदेशालय में संरक्षित प्राचीन सामग्रियों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। पांडुलिपि की तैयारी, लेखन और पेंटिंग तथा ऐतिहासिक अनुसंधान के संबंध में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने पर सात दिवसीय कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

2024-25 के दौरान शुरू की जाने वाली प्रस्तावित प्राथमिकता योजनाएँ इस प्रकार हैं -

"सरायघाट (1671 ई.) की लड़ाई में लाचित बरफुकन की भूमिका का पुनरावलोकन" शीर्षक से एक पुस्तक लिखना और प्रकाशित करना।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित संसाधन व्यक्तियों द्वारा प्राचीन कामरूप पर लिपियों को समझने पर एक कार्यशाला का आयोजन करना, निदेशालय में संरक्षित सभी पांडुलिपियों की सूची बनाना और प्राचीन कामरूप के कम ज्ञात और नए खोजे गए शिलालेखों (रॉक और कॉपर प्लेट शिलालेख) की सूची बनाना।

विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों और संकायों के सहयोग से कार्यशालाओं, क्षेत्रीय कार्यों और अन्य शोध कार्यों को बढ़ावा देना।

सूचना जनसंपर्क एवं मुद्रण एवं स्टेशनरी क्षेत्र -

(आईपीआर विंग)

पत्रकार कल्याण योजना:

पत्रकार कल्याण योजना के अंतर्गत मेरी सरकार। ने 2023-2024 के दौरान दिसंबर, 2023 तक 46 मान्यता प्राप्त और मान्यता प्राप्त पत्रकारों को चिकित्सा उपचार के लिए 15.58 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। अब तक 465 पत्रकारों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को उक्त योजना से 174.61 लाख रुपये की राशि से लाभान्वित किया गया है।

ई-न्यूज़लेटर और स्मृति चिन्ह:

4.4 मिलियन ग्राहकों को असोम बार्टा नामक मासिक ई-न्यूज़लेटर का लाभ मिल रहा है। विभाग ने "मुखमंत्रिर बकृता संकलन, खंड-II" और अन्य स्मारिकाएँ जैसे "ऑनरिंग द पाथफाइंडर्स -सर्वोच्च राज्य नागरिक पुरस्कार", "24 परिवर्तनकारी महीने - उपलब्धियों की एक गाथा", और "2 साल का सुशासन" प्रकाशित किया है। (असमिया और अंग्रेजी दोनों में)

स्कूल शिक्षा क्षेत्र -

वित्तीय वर्ष 2023-24 में, मेरी सरकार ने 419 चाय बागान प्रबंधित स्कूलों के प्रांतीयकरण, 318 स्कूलों के उन्नयन के लिए कदम उठाए हैं। इसके अलावा, सभी सरकारी/प्रांतीय स्कूलों के छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें और मुफ्त वर्दी प्रदान करने जैसे कदम उठाए गए हैं।

आरोहण, पीएम पोषण शक्ति निर्माण, पीएम श्री और नौवीं कक्षा के छात्रों के लिए मुफ्त साइकिल जैसी योजनाओं ने स्कूल शिक्षा क्षेत्र के विकासात्मक पहलू में बड़ी भूमिका निभाई है। साथ ही, एचएसएलसी परीक्षा, 2023 में 75% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को 15,000 रुपये की दर से आनंदराम बरूआ नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जिससे छात्र-छात्राओं को उत्साह मिलेगा। कक्षा IX के कुल 3,69,454 छात्रों को साइकिलें मिलीं, जबकि 27181 उत्तीर्ण उम्मीदवारों को आनंदराम बरूआ नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना 2016 के तहत कक्षा-5 और कक्षा-8 के 33482 लाभार्थी छात्रों के बीच सावधि जमा रसीद की परिसमाप्त परिपक्व राशि 22 दिसंबर 2023 को समारोहपूर्वक वितरण के माध्यम से वितरित की गई है।

आरआईडीएफ के तहत नए स्कूल भवनों का निर्माण और टी गार्डन मॉडल हाई स्कूलों की स्थापना, राज्य के प्रत्येक एलएसी में 126 (सरकारी और प्रांतीय) माध्यमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे का विकास किया गया। साथ ही 12000 से अधिक शिक्षकों, ग्रेड III और ग्रेड IV की नियुक्ति की गई। यह हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

शिक्षण के तौर-तरीकों को विकसित करने की दृष्टि से अधिक बीएड कॉलेजों का निर्माण करना हमारा लक्ष है। एडल्ट एडुकेशन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की सिफारिश के अनुसार न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम शिक्षा क्षेत्र में एक एतिहासिक कदम है।

माध्यमिक शिक्षा के विकासात्मक क्षेत्र में, स्कूल शिक्षा विभाग में सरकार ने छात्रों के लाभ और प्रेरणा के लिए कई योजनाएं प्रस्तावित की हैं। अनुंदोरम बरूआ छात्रवृत्ति, लड़कियों के लिए अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क की माफी, कक्षा IX और X के छात्रों के लिए मुफ्त वर्दी, और कक्षा के छात्रों के लिए मुफ्त साइकिल का वितरण उल्लेखनीय है।

इस बीच, स्कूल शिक्षा विभाग चाय बागान क्षेत्रों में अन्य 100 नए मॉडल स्कूलों की स्थापना के साथ-साथ एससी और एसटी बहुल क्षेत्रों के स्कूलों में चारदीवारी, अतिरिक्त कक्षाओं आदि के निर्माण के लिए भी आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

ग्रेजुएट और पोस्ट टीचर्स की भर्ती के लिए विज्ञापन पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है और भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सरकार द्वारा 2024-25 में जीटी, पीजीटी, ग्रेड-III, IV आदि की रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र -

डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, मेरी सरकार असम के लोगों के उत्थान के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की दिशा में लगन से काम कर रही है।

सेवा सेतु पोर्टल अब 501 नागरिक केंद्रित सेवाओं की मेजबानी करता है, जिनमें से 370 सेवाएँ आरटीपीएस सेवाएँ हैं। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित "असम गवर्नेंस एंड स्मार्ट डिलीवरी प्रोग्राम" के तहत इस संख्या को 1,000+ नागरिक केंद्रित सेवाओं तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। जिसके तहत मोबाइल ऐप-आधारित सेवा वितरण, कियोस्क-आधारित सेवा वितरण, वन-स्टॉप शॉप्स आदि की योजना बनाई गई है।

असम इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (AMTRON) ने DoNEAR की सहायता से, टेक सिटी, बोंगोरा, गुवाहाटी में 5G उपयोग-केस अनुभव केंद्र स्थापित किया, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह का पहला है।

असम सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार निदेशालय अब असम के विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित ई-केवाईसी सेवाओं, सत्यापन और सत्यापन सेवाओं, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, आधार के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण आदि की सुविधा

के लिए एक आधार उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 17वीं सदी के अहोम जनरल लाचित बोरफुकन की 400वीं जन्म जयंती पर 25 भाषाओं में 43 लाख से अधिक निबंधों के संकलन के लिए एक वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया है। जिसके परिणामस्वरूप "हस्तलिखित नोट्स के सबसे बड़े ऑनलाइन फोटो एलबम" के लिए गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया।

भारत के माननीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में NAMO ड्रोन दीदी पहल के तहत, AMTRON ड्रोन स्कूल ने असम के विभिन्न जिलों की 200 महिलाओं के पहले बैच को ड्रोन उड़ान में प्रशिक्षित किया है। पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र में विशिष्ट ड्रोन ट्रेनिंग रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (आरपीटीओ) के रूप में, एमट्रॉन ड्रोन स्कूल कौशल विकास और सशक्तिकरण के लिए एक प्रकाशस्तंभ के रूप में कार्य करता है।

सिंचाई क्षेत्र –

वर्ष 2022-23 के दौरान, लघु एवं सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र में, माननीय प्रधान मंत्री के प्रमुख कार्यक्रम प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना- हर खेत को पानी- एसएमआई के तहत कुल 9 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसके लिए 7605 हेक्टेयर की लक्षित क्षमता के साथ 302.0719 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इसी कार्यक्रम के तहत 753.35 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 19,139 हेक्टेयर की लक्ष्य क्षमता के साथ 23 अन्य एसएमआई योजनाएं प्रस्तावित हैं।

2113 हेक्टेयर की लक्षित क्षमता के साथ 7536.324 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर आरआईडीएफ - XXIX के वित्त पोषण के साथ अन्य 54 सिंचाई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

प्रमुख और मध्यम सिंचाई क्षेत्र में, तीन नई मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ, अर्थात्। ब्रह्मपुत्र घाटी में बुरोई सिंचाई परियोजना, पुथिमारी सिंचाई परियोजना और बुरीसुती सिंचाई परियोजना और बराक घाटी में दो प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं सोनाई सिंचाई परियोजना और रुकनी सिंचाई परियोजना को 56,426 हेक्टेयर की कुल क्षमता बनाने के लिए शुरू करने का प्रस्ताव है।

उपरोक्त के अलावा, विभाग वर्तमान में सतही लघु सिंचाई योजनाएं, टिउब वेल योजनाएं, हाइब्रिड योजनाएं और एसओपीडी (सामान्य, टीएसपी, एससीएसपी), आरआईडीएफ, पीएमकेएसवाई-एआईबीपी आदि के तहत विभिन्न योजनाएं लागू कर रहा है।

प्रभावी सेवा वितरण के लिए योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन और निगरानी के लिए विभागीय अधिकारियों, ठेकेदारों और किसानों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से एक पोर्टल, "सिंचाई परियोजना निगरानी प्रणाली (आईपीएमएस)" काम कर रहा है। यह पोर्टल तीन उपयोगकर्ता-अनुकूल ऐप से जुड़ा है, जैसे किसानों के लिए सिंचाई खेतियाक बंधु ऐप, सिंचाई विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों के लिए आईएनओ सिंचाई ऐप, जिसे Google Play Store से डाउनलोड किया जा सकता है।

सिंचाई विभाग के अंतर्गत सभी योजनाएँ जिओ टैग किया गया है। योजनाओं की नहर एवं कमांड क्षेत्र की मैपिंग भी प्रक्रियाधीन है। एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) के माध्यम से आईएनओ सिंचाई पोर्टल से वास्तविक समय योजना स्थानों को पहले से ही पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल के साथ साझा किया गया है।

लाभार्थी शिकायतों के निवारण के लिए एक विभागीय कॉल सेंटर भी कॉल सेंटर में कॉल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को पूरा करने के लिए कार्य कर रहा है। शिकायतों को पोर्टल में टिकट के रूप में उठाया जाता है जिसे मंडल और उप-मंडल स्तर पर देखा जा सकता है और तुरंत सुधार के लिए संसाधित किया जा सकता है।

प्रमुख और मध्यम सिंचाई क्षेत्र में, दो नई परियोजनाएं अर्थात् हैलाकांडी जिले के अंतर्गत कटाखल सिंचाई परियोजना और कछार जिले के अंतर्गत मदुरा सिंचाई परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव है, जिससे कुल 28,000 हेक्टेयर की क्षमता पैदा होगी। केंद्रीय जल आयोग ने दोनों परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए सर्वेक्षण और जांच का काम शुरू कर दिया है।

लघु एवं सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र में, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी (पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी)-भूजल तक पहुंच के मिशन के तहत, विशेष रूप से छोटे चाय उत्पादकों के लिए चरण-III में 6978 नए टीडब्ल्यू प्वाइंट और चरण-IV में 11775 को लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके लिए 75,192 हेक्टेयर की लक्षित कुल सिंचाई क्षमता के लिए 2239.39 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।

श्रम कल्याण क्षेत्र -

श्रम आयुक्तालय के तहत ई-सेवाओं के स्वचालन के लिए, श्रम आयुक्तालय ने ई-सेवाओं के स्वचालन की शुरुआत करके एक कदम आगे बढ़ाया है, जिसका हाल ही में 25.03.2023 को उद्घाटन किया गया था। तदनुसार, 16 सेवाएं अब पूरी तरह से स्वचालित हैं, जिसमें आवेदन प्रक्रिया पूरी होने पर आवेदकों को तुरंत उनके लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त हो जाते हैं।

अब तक कुल 110104 आवेदन प्राप्त हुए हैं, 104659 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आयुक्तालय के अंतर्गत आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है।

श्रम आयुक्तालय ने बाल श्रम की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से "कार्रवाई माह" के रूप में एक महीने का निरीक्षण अभियान चलाया है और अभियान में 75 बाल/किशोर श्रमिकों को बचाया गया। इसके अलावा, दोषी नियोक्ताओं के खिलाफ 28 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण (आरई एवं सीएस), अधिनियम 1996 के तहत प्रमुख पहल

ई-पंजीकरण: ऑनलाइन पंजीकरण मॉड्यूल ने अधिनियम के तहत असम में निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण की संख्या को 7,02,155 (अक्टूबर 23 के अंत तक) तक बढ़ा दिया।

ऑनलाइन डीबीटी: पंजीकृत लाभार्थी के खाते में सीधे कल्याण लाभ वितरित करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) की प्रक्रिया में एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण के लिए बोर्ड ने पीएफएमएस के साथ

नामांकन किया। अब तक, बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 (नवंबर 23 तक) के दौरान 20,827 पंजीकृत लाभार्थियों को 29,60,54,307.00 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से वितरित की है। स्थापना के बाद से (वित्तीय वर्ष 2012) बोर्ड द्वारा कुल 3,92,62,58,670.00 रुपये की राशि वितरित की गई है।

ट्रांजिट नाइट शेल्टर: असम के गुवाहाटी में एक ट्रांजिट नाइट शेल्टर पूरा हो गया है।

PM-JAY: बोर्ड ने पंजीकृत लाभार्थियों को आयुष्मान भारत (PM-JAY) योजना के तहत चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

कौशल प्रशिक्षण केंद्र: कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग और लार्सन एंड टुब्रो के सहयोग से बोर्ड ने असम के गोगामुख (धेमाजी), बल्लामगुरी (कोकराझार) और धमधमा (नलबाड़ी) में लाभार्थियों और उनके आश्रितों के लिए कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की पहल की है।

वर्ष 2023 के दौरान लगभग 442 नई फ़ैक्टरियाँ पंजीकृत की गईं, जिससे राज्य भर में कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर वैधानिक सुरक्षा के दायरे में लगभग 16,837 फ़ैक्टरी कर्मचारी आ गए।

कुल 18,62,413 ईएसआई लाभार्थियों ने ईएसआईएस डिस्पेंसरी/ अस्पताल और माध्यमिक टाई-अप नर्सिंग होम के माध्यम से परेशानी मुक्त और कैशलेस चिकित्सा लाभ, कामकाजी महिलाओं को मातृत्व लाभ, स्थायी विकलांगता लाभ, अस्थायी विकलांगता, आश्रित लाभ और

अंत्येष्टि लाभ का लाभ उठाया। आईपी की संख्या बढ़ाने के लिए हाल ही में असम के विभिन्न जिलों में 45 स्वास्थ्य और जागरूकता शिविर आयोजित किए गए हैं। ईएसआई लाभार्थियों के अधिक हित के लिए असम के सभी जिलों में कुल 45 माध्यमिक टाई-अप व्यवस्था की गई है।

कार्मिक विभाग -

हमारी सरकार ने असम के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने पर वरिष्ठ रेजिडेंट / ट्यूटर / डेमोंस्ट्रेटर / रजिस्ट्रार / रेजिडेंट सर्जन / रेजिडेंट फिजिशियन के प्रवेश स्तर के पदों पर सरकारी सेवाओं में प्रवेश के लिए ऊपरी आयु सीमा बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। आवेदक की श्रेणी को ध्यान में रखे बिना इसे बढ़ाकर 45 वर्ष कर दिया गया है।

असम के कुछ समुदायों के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने ओबीसी कोटा के भीतर चाय जनजातियों और आदिवासी समुदायों को 3% आरक्षण का लाभ देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा अगले पांच एपीएससी संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में एसीएस और एपीएस कैडर में एक-एक पद ओबीसी कोटा के भीतर मोरान और मोटक समुदायों के लिए भी आरक्षित किया जाएगा।

कार्मिक विभाग के तहत असम लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2023 के दौरान 25 कार्यक्रम आयोजित किये। विभिन्न लिखित/स्क्रीनिंग परीक्षाओं में नियुक्ति के लिए 512 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई। आयोग ने हाल ही में 913 की सिफारिश की है। एसीएस (जूनियर ग्रेड) और संबद्ध सेवाओं में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की सूची और अनुशंसित उम्मीदवारों को शीघ्र ही नियुक्ति जारी की जाएगी। कार्मिक विभाग के तहत असम लोक सेवा आयोग अगले संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए

एसीएस (जूनियर ग्रेड) और संबद्ध सेवाओं के 235 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन देने वाला है।

तृतीय श्रेणी पदों के लिए राज्य स्तरीय भर्ती आयोग (एसएलआरसी) ने 3/5/2023 को अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है और विभिन्न विभागों के तहत विभिन्न तृतीय श्रेणी पदों पर नियुक्ति के लिए 11,316 उम्मीदवारों का चयन किया गया है।

चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए राज्य स्तरीय भर्ती आयोग (एसएलआरसी) ने 4 मई 2023 को अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है और विभिन्न विभागों के तहत विभिन्न चतुर्थ श्रेणी पदों पर नियुक्ति के लिए 14,281 उम्मीदवारों का चयन किया गया है।

राज्य स्तरीय भर्ती आयोग (एसएलआरसी) ने तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए 7600 पदों के लिए विज्ञापन दिया है। असम सरकार के विभिन्न प्रतिष्ठानों/विभागों के तहत चालू वर्ष के दौरान क्रमशः तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों (अस्थायी) और 5000 रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पदों (अस्थायी) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

विद्युत क्षेत्र –

तीन बिजली उपयोगिताओं- एपीडीसीएल, एपीजीसीएल और एईजीसीएल द्वारा सफलतापूर्वक कार्यान्वित कई परियोजनाओं की मदद से पिछले कुछ वर्षों में असम की बिजली आपूर्ति की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। वर्तमान में विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता ग्रामीण क्षेत्र में 23.49 घंटे तथा शहरी क्षेत्र में 23.49 घंटे हो गयी है।

एपीडीसीएल ने असम के 26,235 राजस्व गांवों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है और सभी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के तहत ऐसे

गांवों के 37,53,784 परिवारों को बिजली कनेक्शन भी प्रदान किया है। यह योजनाए है- आरजीजीवीवाई, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), 'डीडीयूजीजेवाई - नई' और सौभाग्य।

अब तक, एपीडीसीएल ने राज्य में 11 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर सफलतापूर्वक स्थापित किए हैं। इससे मीटर रीडिंग और बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है।

एपीडीसीएल आरडीएसएस और एडीएसईएलआर परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है और पिछले 2 वर्षों में एटीएंडसी घाटे को 26.56% से 16.2% तक काफी कम करने में सक्षम रहा है।

असम पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (APGCL) राज्य में बिजली उत्पादन को अधिकतम करने के लिए जिम्मेदार है। निर्माणाधीन 120 मेगावाट लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना दिसंबर, 2024 के भीतर पूरी होने की उम्मीद है। असम के दिमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग जिलों में स्थित, यह परियोजना एडीबी द्वारा वित्त पोषित है।

एपीजीसीएल 24 मेगावाट की कार्बी लांगपी मिडिल-II हाइड्रो पावर परियोजना भी कार्यान्वित कर रहा है। असम की माननीय कैबिनेट ने अक्टूबर, 2023 में असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में 417.32 करोड़ रुपये की लागत से परियोजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा, एपीजीसीएल और ओआईएल लगभग 620 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन में लगे हुए हैं।

असम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एईजीसीएल) राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी है जो विद्युत ऊर्जा के प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2023 में एईजीसीएल ने अपनी ट्रांसमिशन क्षमता 7826 एमवीए से बढ़ाकर 2022 से 9120 एमवीए कर दी है। वर्ष 2023 में ईएचवी सबस्टेशनों की संख्या 73 से बढ़कर 80 हो गई है।

एम्स, गुवाहाटी, परिसर में 132/33 केवी सब-स्टेशन के निर्माण ने 01/01/2023 से संस्थान को विश्वसनीय गुणवत्ता वाली बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की है।

एनईआरपीएसआईपी (उत्तर पूर्वी क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना) के तहत, वर्ष 2023 में क्रमशः सिलापाथर, तेजपुर और हाजो में 3 (तीन) उप-स्टेशन चालू किए गए हैं। मेरी सरकार वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एईजीसीएल की निम्नलिखित गैर-बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (एआईआईबी वित्त पोषित) को शुरू करने का प्रस्ताव कर रही है। वह इस प्रकार का है-

ए) 2x100 एमवीए, 220/132 केवी रंगिया जीएसएस का 2x200 एमवीए ऑटो-ट्रांसफार्मर (चरण-I) द्वारा संवर्द्धन।

बी) 132 केवी श्रीकोना-पंचग्राम ट्रांसमिशन लाइन का पुनरुद्धार।

सी) संबंधित टर्मिनल उपकरण के साथ 132 केवी नाजिरा-जोरहाट (गार्मूर) लाइन के दूसरे सर्किट की स्ट्रिंगिंग।

डी) बस प्रणाली के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के साथ 132kV एपीएम जीएसएस पर 132kV लाइन बे का निर्माण। (चरण 1)।

लोक निर्माण सड़क क्षेत्र -

सड़क परिवहन की समतापूर्ण सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका है और राज्य के सामाजिक और आर्थिक एकीकरण और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

वर्ष 2024 की शुरुआत लोक निर्माण सड़क विभाग में कार्यान्वयन के तहत बड़ी संख्या में विकासात्मक परियोजनाओं के साथ हुई है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को असम में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। कुशल परिवहन के लिए राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को उच्च गति वाले सड़क गलियारों में सुधार और उन्नयन करके सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सड़क बुनियादी ढांचे को विकसित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया असोम माला कार्यक्रम भी चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत, पलासबारी मिर्जा चंदुबी रोड, घागरापार दामोदरधाम बिजुलीघाट रोड, सिंगीमारी सुआलकुची रोड सहित महत्वपूर्ण सड़कें पूरी हो चुकी हैं और महत्वपूर्ण पुलों के साथ-साथ बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण सड़कें निर्माणाधीन हैं।

एडीबी द्वारा वित्त पोषित एएससीसीआईपी परियोजना के तहत, दिमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग और पश्चिम कार्बी आंगलोंग पहाड़ी जिलों, बीटीआर और बराक घाटी क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़कों को लिया गया है।

नाबार्ड की नई योजना एनआईडीए के तहत, कोकराझार से रूपसी हवाई अड्डे (कोकराझार बाईपास), रोवटा मिसामारी रोड, डिराकगेट-पेंगेरी रोड, गोहपुर धौलपुर रोड और डेरगांव गोलाघाट रोड सहित 5 सड़क गलियारे शुरू किए गए हैं।

नाबार्ड से वित्त पोषण के साथ NIDA के माध्यम से असोम माला 2.0 के तहत एसएच और एमडीआर के 1000 किमी के अन्य क्षेत्रों को कवर करने वाली परियोजनाओं का एक नया बैच शुरू किया जा रहा है।

चार सड़क योजनाओं का एक समूह, अर्थात् (i) मुख्यमंत्रीर पाकीपथ निर्माण अचानी, (ii) मुख्यमंत्री उन्नोतो पाकीपथ निर्माण अचानी, (iii) मुख्यमंत्रीर मोथौरी पकीकरण अचानी और (iv) मुख्यमंत्री पथ नबीकरण अचानी। असम के सभी जिलों को कवर करना शुरू कर दिया गया है। कार्य ठेकेदारों को सौंप दिया गया है और प्रगति पर है।

गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ने वाले ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल के निर्माण की परियोजना चल रही है। पलाशबाड़ी को सुआलकुची से जोड़ने वाला ब्रह्मपुत्र नदी पर एक और प्रमुख पुल बन रहा है।

विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित असम रेजिलिएंट रूरल ब्रिज प्रोजेक्ट में 1000 से अधिक पुलों के निर्माण, चौड़ीकरण और पुनर्वास का काम शुरू किया गया है।

जिले में आपदा प्रतिरोधी धमनी सड़क नेटवर्क विकसित करने के लिए दिमा हसाओ जिले में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एक नई परियोजना शुरू की गई है।

विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्र -

मेरी सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और राज्य में एक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

राज्य में नीति निर्देशित कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए, सरकार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग एक राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है। इससे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के माध्यम से राज्य के समग्र विकास में मदद मिलेगी।

हमारे राज्य में पहली बार, वित्त विभाग ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण और वन विभाग के तकनीकी सहयोग से 14 विभागों के लिए ग्रीन बजट शुरू किया है। बजट टैगिंग उन योजनाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद करती है जो जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, शमन और पर्यावरणीय स्थिरता में मदद करती हैं। इस पहल से पर्यावरण संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी।

वर्तमान में, बक्सा, बिश्वनाथ, चराइदेव, धुबरी, डिब्रूगढ़, गोवालपारा, हैलाकांडी, होजाई, करीमगंज, सोनितपुर और उदालगुरी में 11 जिला विज्ञान केंद्रों का निर्माण कार्य चल रहा है और अमीनगांव, बोंगाईगांव, दीफू, कलियाबोर, माजुली और सिलचर में 6 जिला विज्ञान केंद्र और तारामंडल।

एसटी और सीसी विभाग में सरकार ने उन छात्रों का चयन करने के लिए मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा संधान की घोषणा की है जो विज्ञान को अपने करियर के रूप में अपनाने के इच्छुक हैं। और जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कौशल दिखाया है ताकि उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए भारत के चयनित प्रतिष्ठित एस एंड टी संस्थानों में ले जाया जा सके ताकि नए आविष्कारों और नवाचारों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हो सके। गुवाहाटी तारामंडल प्रबंधन सोसायटी (जीपीएमएस), असम सरकार,

आईआईटी गुवाहाटी के सहयोग से "एवं" (Evam)नाम से एक अभूतपूर्व शैक्षिक मेटावर्स बना रही है, जो घर्षण सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर गहन सीखने के अनुभव प्रदान करेगा। मानव शरीर रचना विज्ञान, गुरुत्वाकर्षण, वायु प्रतिरोध आदि। इवाम पृथ्वी से परे अपनी शैक्षिक पहुंच का विस्तार करता है, जिससे छात्रों को मंगल, शुक्र और बृहस्पति जैसे अन्य ग्रहों पर इन अवधारणाओं का पता लगाने की अनुमति मिलती है। यह उद्यम इंटरैक्टिव और इंटरप्लेनेटरी शिक्षा में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है और इसे जल्द ही जनता के लिए खोल दिया जाएगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता क्षेत्र -

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग राज्य के महत्वपूर्ण विभागों में से एक है जो अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, तृतीय लिंग समुदाय के कल्याण के लिए विभिन्न बुनियादी ढांचे और लाभार्थी संबंधी योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही राज्य में मादक और मनोदैहिक पदार्थों से संबंधित मुद्दों को भी संबोधित करता है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय के तहत, मेरी सरकार निम्नलिखित योजनाएं लागू कर रही है-

ए) दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना को अब असम कौशल विकास मिशन और रोजगार और शिल्पकार प्रशिक्षण निदेशालय, असम के सहयोग से लागू करने का प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य वित्तीय अनुदान के स्थान पर लाभार्थियों को कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना है।

बी) मेडिकल और तकनीकी पाठ्यक्रम करने वाले प्रत्येक विकलांग छात्र को 2,400/- रुपये वार्षिक और 36,000/- रुपये की राशि के लिए विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

ग) विशिष्ट विकलांगता आईडी (यूडीआईडी) परियोजना कार्यान्वित की जा रही है और अब तक, असम राज्य में कुल 1,85,595 यूडीआईडी कार्ड बनाए गए हैं।

घ) तृतीयो निवास, राज्य में बेघर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के 50 कैदियों की क्षमता वाला एक आश्रय गृह, सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की गई निधि से चलाया जाता है। आश्रय गृह में एक सुसज्जित कौशल विकास केंद्र भी है जिसमें ब्यूटीशियन पाठ्यक्रम, सिलाई और टेलरिंग पाठ्यक्रम आदि शामिल हैं।

छात्रवृत्ति योजनाएँ:- एसओपीडी बजट के तहत कक्षा I से VIII तक के छात्रों को प्रति वर्ष 1200/- रुपये की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। चालू वर्ष के दौरान 1875 अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए चुना गया है।

सफाई कर्मचारियों और मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए विकास योजना: - मेरी सरकार राज्य के नगर निगम बोर्डों को वाहन माउंटेड सेसपूल एम्प्टीयर खरीदने और वितरित करने का प्रस्ताव करती है, जहां बोर्ड वाहनों के संचालन के लिए सफाई कर्मचारियों / मैनुअल स्कैवेंजर्स को नियुक्त करेंगे।

मृदा संरक्षण क्षेत्र -

मृदा संरक्षण विभाग भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) के दिशानिर्देशों के अनुसार 2015-16 से असम में केंद्र

प्रायोजित योजना, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक को लागू कर रहा है।

वर्ष 2021-22 में, भूमि संसाधन विभाग (DoLR), भारत सरकार ने WDC-PMKSY 2.0 के तहत असम के लिए 136,573.00 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 31 वाटरशेड परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 5 वर्षों की अवधि के लिए कुल परियोजना लागत 310.60 करोड़ रुपये है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) के तहत किए गए कार्यों में 157 फार्म तालाब, 82 चेक डैम, 12 नाला बांध, 11 परकोलेशन टैंक, 144 अमृत सरोवर और 176.46 हेक्टेयर भूमि शामिल है। वनीकरण, 5,470.52 हेक्टेयर भूमि को मिट्टी और नमी संरक्षण गतिविधियों के तहत कवर किया गया है और 235.71 हेक्टेयर भूमि को बागवानी वृक्षारोपण के तहत लाया गया है, असम के तीन पहाड़ी जिलों में पानी के पारंपरिक स्रोत के पुनरुद्धार के लिए 82 स्प्रिंगशेड गतिविधियों को लागू किया गया है। जल सुरक्षा में योगदान और जलवायु लचीलापन बढ़ाने के लिए। आजीविका गतिविधियों के तहत 2441 एसएचजी और उत्पादन प्रणाली के तहत अब तक 3062 व्यक्तियों और उपयोगकर्ता समूहों को समर्थन दिया गया है।

अगले वर्ष के लिए योजना: विभाग ने प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम), उत्पादन प्रणाली, आजीविका गतिविधियों के अलावा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन कार्यों के लिए 138.89 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि के साथ 2024-25 के लिए वार्षिक कार्य योजना विकसित की है- प्रबंधन लागत, निगरानी और मूल्यांकन, संस्थान और क्षमता निर्माण आदि।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग-

मेरी सरकार ने 15.4 एकड़ में फैले खेल परिसर के साथ 30,000 दर्शकों के लिए फीफा - श्रेणी 02 सुविधाओं के साथ एक प्रतिष्ठित, अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव दिया है। फुटबॉल सुविधाओं के अलावा, स्टेडियम में इनडोर प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए 6 बैडमिंटन कोर्ट, एक ओलंपिक आकार का स्विमिंग पूल, दस लेन की 10 मीटर शूटिंग रेंज, एक वुशु और तायक्वोंडो क्षेत्र, एक स्क्वैश कोर्ट और एक टेबल टेनिस कोर्ट होगा। यहां 1, 2 और 3 बिस्तरों वाले 180 बिस्तरों वाली आवासीय प्रशिक्षण सुविधा भी होगी। 1200 कारों के लिए एक ढकी हुई कार पार्किंग की सुविधा भी होगी और 15000 दर्शकों के लिए ढकी हुई छत की सुविधा भी परियोजना के घटकों का हिस्सा है।

2023-24 के दौरान गतिविधियाँ/उपलब्धियाँ:

मेरी सरकार द्वारा 2023-24 में एक घोषणा की गई थी कि खेल और युवा कल्याण विभाग जमीनी स्तर के मेगा खेल आयोजन "खेल महारण" की मेजबानी करेगा, जिसमें 5 खेल अनुशासन- एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल और खो-खो शामिल होंगे। इसका उद्देश्य जीपी स्तर, एलएसी स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान करना है। तदनुसार, खेल महारान की शुरुआत 1 नवंबर 2023 को जीपी स्तर पर प्रतियोगिताओं के साथ हुई, उसके बाद एलएसी स्तर की प्रतियोगिताओं और जिला स्तर की प्रतियोगिताओं के साथ हुई। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं 28 जनवरी से 6 अलग-अलग स्थानों पर आयोजित की जाएंगी। जीपी स्तर पर खेल महारण में 27.26 लाख से अधिक खिलाड़ियों/एथलीटों ने भाग लिया है, जिससे यह राज्य में अब

तक का सबसे बड़ा जमीनी स्तर का खेल आंदोलन बन गया है। 19 वर्ष से कम श्रेणी में लगभग 70,000 खिलाड़ियों और 19 वर्ष से उपर श्रेणी में लगभग 40,000 खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के कारण जीपी स्तर पर संभावित खिलाड़ियों के रूप में पहचाना गया है।

चाय जनजातियाँ और आदिवासी कल्याण क्षेत्र -

चाय जनजातियों और आदिवासी समुदाय के बीच शिक्षा परिदृश्य को प्रोत्साहित करने और सुधारने के लिए, राज्य सरकार। विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति जारी कर रहा है।

सिविल सेवा, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कर्मचारी चयन समिति (स्नातक स्तर), बैंकिंग (परिवीक्षाधीन अधिकारी) आदि जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को कोचिंग, "उच्च अध्ययन के लिए कोचिंग" योजना के तहत प्रदान की जाती है।

असम की चाय जनजातियों और आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए, सरकार। काजीरंगा में "असम चाह जनगुस्तिया समन्नय कलाक्षेत्र" के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। वर्तमान सरकार ने असम के सभी चाय बागानों में 1.5 करोड़ रुपये की प्रत्येक इकाई लागत के साथ "जगन्नाथ सामुदायिक हॉल सह कौशल केंद्र" के निर्माण की एक महत्वाकांक्षी योजना भी शुरू की है। सेंटर में कौशल विकास की भी सुविधा होगी. सामुदायिक भवन का उपयोग विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों, विवाह और अन्य समारोहों के लिए किया जाएगा।

चाय जनजातियों और आदिवासी समुदाय के बीच खेलों के प्रसार के लिए, सरकार ने सोनितपुर जिले के रंगपारा, तिनसुकिया जिले के छोटा तिंगराई और चराइदेव जिले के सोनारी में तीरंदाजी अकादमी का निर्माण कार्य शुरू किया है। खेल अकादमियाँ पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में हैं। इस वर्ष, सरकार ने समुदाय की युवा फुटबॉल प्रतिभाओं को निखारने और विकसित करने के लिए "मुख्यमंत्री चाय जनजाति और आदिवासी फुटबॉल टूर्नामेंट (अंडर-19 लड़के)"-एक राज्य स्तरीय लड़कों का फुटबॉल टूर्नामेंट भी आयोजित किया है।

चाय बागानों में दी जाने वाली बिजली वाणिज्यिक दर के अंतर्गत आती है, जिससे लाइन में रहने वाले चाय बागान श्रमिकों पर भारी बोझ पड़ता है। बोझ को कम करने के साथ-साथ भारी बिजली बकाया को माफ करने के लिए, इस विभाग ने एपीडीसीएल को मार्च 2023 तक बकाया माफ करने के लिए 102.51 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

चाय जनजाति और आदिवासी समुदाय को MOBC के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वे अन्य ओबीसी समुदायों के साथ आरक्षण साझा करते हैं। चूंकि वे श्रेणी के भीतर प्रतिस्पर्धा करने और आरक्षण का लाभ लेने में असमर्थ हैं, इसलिए इस विभाग ने कदम उठाया है और सरकार ने अक्टूबर, 2023 के महीने में विशेष रूप से चाय जनजातियों के लिए ओबीसी कोटा के भीतर 3% आरक्षण के प्रावधान की घोषणा की है। ग्रेड-III और ग्रेड-IV पदों पर राज्य सरकार की नौकरियों में आदिवासी समुदाय।

चाय जनजाति एवं आदिवासी कल्याण विभाग की लाभार्थी संबंधी योजनाओं को अधिक पारदर्शी, त्रुटिरहित एवं समयबद्ध बनाने के

लिए विभिन्न छात्रवृत्ति एवं लाभार्थी संबंधी योजनाओं में SIRISH ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इस कदम ने हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री - श्री नरेंद्र मोदीजी के डिजिटल इंडिया मिशन के दृष्टिकोण के अनुरूप, चाय जनजातियों और आदिवासी समुदाय के छात्रों और लाभार्थियों को डिजिटल मोड को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है।

पर्यटन क्षेत्र -

राज्य की अपार पर्यटन क्षमता का दोहन करने के लिए, जो न केवल रोजगार के अवसर पैदा करेगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देगा, मेरी सरकार। ने निम्नलिखित योजनाएं/गतिविधियां शुरू की हैं:

पुण्य धाम यात्रा: इस योजना के तहत असम के 58 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के तीर्थयात्री अब तक देश के कुछ लोकप्रिय तीर्थ स्थलों जैसे पुरी, वृंदाबन, अजमेर शरीफ, वैष्णो देवी आदि की यात्रा कर चुके हैं।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की चिकित्सा और कल्याण पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रोड मैप की भावना में। भारत के पर्यटन विभाग, असम सरकार ने अमीनगांव, उत्तरी गुवाहाटी में चिकित्सा पर्यटन सुविधाएं स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। असम सरकार के पर्यटन विभाग ने अमिनगाँव में एक मनोरंजक पार्क सहित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ एक आधुनिक यात्रीनिवास स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। दोनों प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है।

हमारी सरकार द्वारा लिए गए प्रमुख नीतिगत निर्णय: काजीरंगा में हयात ग्रुप ऑफ होटल्स के साथ एक 5-सितारा होटल स्थापित करने

के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, एक कौशल विकास केंद्र, जो पर्यटन और पर्यटन में लगे व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए टाटा स्ट्राइव के सहयोग से सोनापुर में स्थापित किया गया है। आतिथ्य क्षेत्र, टाटा समूह के साथ काजीरंगा में दो हाई-एंड टी टूरिज्म रिसॉर्ट्स की स्थापना के लिए और असम पर्यटन के लिए ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म ईज माई ट्रिप के साथ असम में पर्यटन बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं।

पर्यटन आकर्षण की क्षमता के रूप में असम की जनसांख्यिकीय विविधता और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए; पर्यटन विभाग, असम सरकार ने भारत और विदेशों में असम के लोगों की विविध संस्कृति और आजीविका को प्रदर्शित करने के लिए ब्रह्मपुत्रा कार्निवल, बिहू बिनोंदिया, अंबुबाची मेला आदि जैसे प्रमुख आयोजन किए हैं।

परिवर्तन और विकास विभाग

असम सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के मामले में उच्च वृद्धि दर्ज करने वाले संभावित राज्यों में से एक है। अग्रिम अनुमान के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 (एई) के लिए मौजूदा कीमतों पर असम के लिए नाममात्र जीएसडीपी वित्त वर्ष 2022-23 (क्यूई) में 4.93 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 5.65 लाख करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंचने की संभावना है। पिछले वर्ष की तुलना में 14.7 प्रतिशत की वृद्धि। अनुमानित अनुमान के अनुसार, वर्ष 2024-25 के लिए मौजूदा कीमतों पर राज्य की जीडीपी 6.39 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2022-23 (क्यूई) में असम की नाममात्र

आर्थिक वृद्धि 19.9 प्रतिशत होने का अनुमान है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह 16.1 प्रतिशत है।

वित्त वर्ष 2023 -24 (एई) के लिए मौजूदा कीमतों पर असम की प्रति व्यक्ति आय 1,35,787 रुपये होने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 (क्यूई) के लिए 1,20,336 रुपये की तुलना में 12.84 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

परिवहन क्षेत्र -

हरित परिवहन और कम कार्बन उत्सर्जन के लिए जैसे- असम की वाहन परिमार्जन नीति, 2022, पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले "जीवन के अंत" वाहनों को स्वैच्छिक रूप से प्रस्तुत करने को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं। साथ ही एंड ऑफ लाइफ वाहनों के परिचालन को उचित तरीके से तोड़ने और स्क्रैप करने को भी सुनिश्चित किया जाएगा।

वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप को दूर करने के लिए, निजी मोड में 2 स्वचालित परीक्षण स्टेशन और एएसटीसी के तहत 4 पीपीपी में स्थापित किए जा रहे हैं। दूसरी ओर गुवाहाटी के ळखरा स्थित आईएसबीटी में एक MoRTH-वित्त पोषित निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र का निर्माण चल रहा है।

असम सरकार ने प्रदूषण मुक्त असम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को लागू करने की शुरुआत की है, "उत्पादन मुक्त एक्सोम" जहां प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले हस्तक्षेप असम में बड़े पैमाने पर पारगमन के भविष्य को फिर से आकार देंगे। गुवाहाटी शहर और इसके आस-पास के क्षेत्रों में 200 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) तैनात

किए गए हैं। इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने 1 जनवरी 2024 को नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के साथ किया था, जो एक संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में यात्रा और कैशलेस लेनदेन को सरल बनाना है।

जनजातीय कार्य विभाग-

मेरी सरकार राज्य में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के विभिन्न सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समुदायों के सशक्तिकरण और सर्वांगीण विकास के लिए लगातार उपयुक्त योजनाएं, नीतियां और विशेष विकास पैकेज अपना रही है।

छात्रवृत्ति: 2023-24 के दौरान, एसटी छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 171.00 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है।

प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAAGY): सरकार ने की थी

कम से कम 50% आदिवासी आबादी और 500 एसटी आबादी वाले कुल 1700 गांवों की पहचान की गई ताकि उन्हें मॉडल गांवों (आदर्श ग्राम) में बदल दिया जा सके। कुल 1700 गांवों को चिन्हित कर योजना के तहत कार्यों का क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है।

12 गांवों को कवर करने वाले 1167 गांव। गोलपारा, सिबसागर, बक्सा, कोकराझार, चिरांग, जोरहाट/माजुली, नागांव, कामरूप (एम), लखीमपुर, कार्बी आंगलोंग, दिमा हसाओ और धेमाजी जिलों में पहले ही काम शुरू हो चुका है। फार्म बैंक का निर्माण, गांवों का सौर विद्युतीकरण,

गांवों के बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करना जैसी गतिविधियां संबंधित विभागों के साथ मिलकर कार्यान्वित की जा रही हैं।

जल संसाधन क्षेत्र -

जल संसाधन विभाग राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (आरबीए), 1987, 2002 और 2012 की राष्ट्रीय जल नीतियों की सिफारिश के अनुसार बाढ़ और नदी तट कटाव प्रबंधन योजनाओं को लागू कर रहा है और 50% से अधिक को उचित सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। 1954 से तटबंध प्रणालियों के निर्माण और कटाव संरक्षण कार्यों के माध्यम से 31.50 लाख हेक्टेयर के बाढ़ प्रवण क्षेत्र का।

विश्व बैंक के तहत असम इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोग्राम (एआईआरबीएमपी): विभाग ने पहले ही 125 मिलियन डॉलर की समकक्ष फंडिंग के साथ 500 मिलियन डॉलर की ऋण राशि के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना "असम इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोग्राम (एआईआरबीएमपी)" शुरू कर दी है। इस कार्यक्रम में, दो व्यापक बाढ़ प्रबंधन योजनाएँ शुरू की गई हैं, एक बुरीदेहिंग नदी पर और दूसरी मानस बेकी नदी पर।

इसके बाद, जियाभराली, गैनादी-जियाधल, भोगदोई, सिंघला और जतिंगा जैसी अन्य महत्वपूर्ण नदियों के लिए वित्त पोषण पर विचार किया जाएगा।

एशियाई विकास बैंक के तहत जलवायु लचीला ब्रह्मपुत्र एकीकृत बाढ़ और नदी तट कटाव जोखिम प्रबंधन परियोजना (CRBIFRERMP):

WRD ने $400M के ADB ऋण और $100M के समकक्ष वित्त पोषण के साथ "जलवायु लचीला ब्रह्मपुत्र एकीकृत बाढ़ और नदी तट

कटाव जोखिम प्रबंधन परियोजना (CRBIFRERMP)" का प्रस्ताव दिया है। परियोजनाएं मुख्य धारा ब्रह्मपुत्र में बाढ़ और कटाव प्रबंधन के लिए लक्षित हैं और 9 जिलों में 4 उप-परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। परियोजनाओं को केंद्रीय जल आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति ने मंजूरी दी है।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं विकास विभाग -

अल्पसंख्यक कल्याण और विकास विभाग (डब्ल्यूएमडी) भाषाई अल्पसंख्यकों और असम के चार चापोरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों सहित अल्पसंख्यकों के मामलों से निपटने वाला प्रशासनिक विभाग है। विभाग का कार्य अल्पसंख्यक समुदायों (भाषाई अल्पसंख्यकों सहित) और चार क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाना और निष्पादित करना है ताकि इन समुदायों को मुख्य धारा के बराबर लाने में सक्षम बनाया जा सके।

स्वदेशी समुदायों की पहचान का संरक्षण: वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, हमारी सरकार ने वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कौशल विकास में उन्हें सशक्त बनाने के लिए स्वदेशी असमिया मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों और अग्रणी नागरिकों के साथ "अलाप अलोचना" नामक एक नई पहल की है। इसके अंतर्गत सांस्कृतिक पहचान, महिलाओं का उत्थान, जनसंख्या स्थिरीकरण आदि शामिल है। 7 उप-समूहों का गठन किया गया और रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तदनुसार, कैबिनेट ने स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय समावेशन शिक्षा, जनसंख्या स्थिरीकरण, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में उनके विकास के लिए असम के स्वदेशी असमिया

मुस्लिम समुदाय गोरिया, मोरिया, देशी, जोल्हा और सैयद की पहचान के संबंध में मामले को आदि को मंजूरी दी गई है।

अल्पसंख्यक समुदायों का कल्याण: वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, विभाग ने 21 मॉडल आवासीय विद्यालय (एमआरएस), 46 सद्भाव मंडप, 32 सामान्य सेवा केंद्र, 19 स्वच्छता और पेयजल सुविधाएं और 14 का निर्माण कार्य शुरू किया है। पीएमजेवीके (केंद्र प्रायोजित योजना) के तहत मार्केट शेड और जिनमें से 6 एमआरएस, 16 सद्भाव मंडप, 14 सामान्य सेवा केंद्र, 10 स्वच्छता और पेयजल सुविधाएं और 7 मार्केट शेड पूरे हो चुके हैं।

वित्तीय वर्ष, 2023-24 के लिए, असम अल्पसंख्यक विकास बोर्ड बेरोजगार युवाओं को ई-रिक्शा का वितरण, असम में एसएचजी को फैशन डिजाइन मशीन का वितरण, एसएचजी को स्वचालित पेपर प्लेट बनाने की मशीन का वितरण जैसी विभिन्न विकास योजनाओं को लागू करने जा रहा है। असम में, असम में अल्पसंख्यक महिला लाभार्थियों को सिलाई मशीन का वितरण, यूपीएससी के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए कोचिंग (12 महीने), एसओपीडी के तहत कौशल उन्नयन के लिए अल्पसंख्यक लड़कियों को फुटबॉल के लिए कोचिंग (12 महीने) आदि सुविधा प्रदान करने की पहल की जा रही है।

महिला एवं बाल विकास क्षेत्र -

हमारी सरकार ने महिला एवं बाल विकास से संबंधित कई योजनाएं और प्रमुख कार्यक्रम लागू कर रही है। इसमें महिला

सशक्तिकरण, बाल संरक्षण और किशोर लड़कियों का समग्र विकास, स्वास्थ्य और कल्याण आदि शामिल है।

प्रमुख उपलब्धि/नई पहल:

आंगनवाड़ी सेवाएं:- आंगनवाड़ी सेवाएं एकमात्र प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जो 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की जरूरतों को पूरा करती है। यह छोटे बच्चों को पूरक पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, प्राइमारी स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा आदि जैसी सेवाओं के एकीकृत पैकेज प्रदान करता है। पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए भी कार्यक्रम का विस्तार किया गया है। वर्तमान में, 61,845 आंगनवाड़ी केंद्र कार्य कर रहे हैं, जिसमें बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं सहित 37,40,542 लाभार्थी शामिल हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र वह मंच हैं जो गांवों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करते हैं।

मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों के अंतर्गत रैंप, बच्चों के अनुकूल शौचालय, अलग रसोई भंडारण और विद्युतीकरण और पीने के पानी के साथ बच्चों के अनुकूल फर्नीचर की सुविधाएं हैं। अब तक 999 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जा चुका है। शेष 3220 मॉडल आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को टर्मिनल लाभ प्रदान करना: सरकार ने 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 4.00 लाख रुपये, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (मिनी) को 3.00 लाख रुपये और आंगनवाड़ी

सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये की दर से टर्मिनल लाभ का प्रावधान किया है, जो 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी है। इस पहल के रूप में, 1,688 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और 1,703 आंगनवाड़ी सहायकों को कैलेंडर वर्ष (2023) के दौरान टर्मिनल लाभ प्रदान किया गया था।

महिला कल्याण:

भारत सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं जो महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं और उनका उद्देश्य उन्हें उचित सामाजिक सम्मान प्रदान करना है। राज्य में लागू की गई विभिन्न योजनाएं जैसे वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), शक्ति सदन (उज्ज्वला और स्वाधीन गृह), कामकाजी महिला छात्रावास (डब्ल्यूडब्ल्यूएच), प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) आदि महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण में मदद कर रही हैं।

खान एवं खनिज क्षेत्र –

खान एवं खनिज विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 4121.36 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड उच्च रॉयल्टी संग्रह का एहसास किया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 62.33% की वृद्धि थी। चालू वर्ष के दौरान नवंबर तक रॉयल्टी संग्रह 2535.89 करोड़ रुपये है।

इतिहास में पहली बार कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की क्षमता ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट, निचले असम के साथ-साथ दिमा-हसाओ जिले में भी पाई गई है जो पहले केवल ऊपरी असम और बराक घाटी तक ही सीमित था। इन क्षेत्रों में अन्वेषण के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड को ब्लॉक आवंटित किए गए हैं।

खनिज संसाधनों के उपयोग के लिए कार्बी आंगलोंग, दिमा हसाओ जिले और गोलाघाट जिलों में खनन क्षेत्रों के लिए सिलिमेनाइट और चूना पत्थर जैसे प्रमुख खनिजों के लिए खनन पट्टा विलेख निष्पादित किए गए हैं। खान एवं खनिज विभाग ने क्वार्टजाइट के 8(आठ) ब्लॉक और चाइना क्ले के 2(दो) ब्लॉक की भी 40.5 करोड़ रुपये के ठोस मूल्य पर नीलामी की है।

इतिहास में पहली बार, दिमा हसाओ जिले में चूना पत्थर के छह ब्लॉक और धुबरी जिले में लौह अयस्क के एक ब्लॉक को राष्ट्रीय स्तर की नीलामी में रखा गया है। उम्मीद है कि इससे राज्य के खजाने में सालाना 1004.52 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी। ग्रेनाइट, ग्लास-रेत और बलुआ पत्थर के लघु खनिजों की आगे की नीलामी प्रक्रिया में है।

उद्योग वाणिज्य एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग -

हमारे राज्य असम मजबूत जीएसडीपी विकास दर प्रदर्शित करते हुए देश की अगली बड़ी विकास कहानी के रूप में उभरा है। इस संबंध में, उद्योग सामाजिक-आर्थिक स्तर को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। 1000 से अधिक चाय बागानों और इस उद्योग में 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने के साथ, चाय उद्योग वास्तव में असम की 200 साल पुरानी औद्योगिक विरासत का ध्वजवाहक है।

भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े तटवर्ती उत्पादकों में से असम एक है। हमारे पास डिगबोई में दुनिया की सबसे पुरानी परिचालन तेल रिफाइनरी और परिचालन तेल क्षेत्र है। 7.6 एमटीपीए की कच्चे तेल शोधन क्षमता के साथ, असम इस क्षेत्र के लिए एक शोधन केंद्र बनने के लिए तैयार है।

असम सरकार ने हाल ही में 15 निजी क्षेत्र की परियोजनाओं से निवेश का इरादा हासिल करते हुए इथेनॉल क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। विशेष रूप से, इनमें से 7 परियोजनाओं को तेल विनिर्माण कंपनियों के एक प्रमुख संघ द्वारा विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं के रूप में चुना गया है। ये सात इकाइयां सामूहिक रूप से 1,154 करोड़ रुपये के पर्याप्त नियोजित निवेश के साथ 970 किलो लीटर प्रति दिन (केएलडी) का वार्षिक उठाव प्रस्तावित करती हैं। यह महत्वाकांक्षी पहल स्थानीय अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव डालने के लिए तैयार है, जिससे लगभग 5,000 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। क्षेत्र की वृद्धि और व्यवहार्यता को और बढ़ावा देने के लिए, इनमें से 3 परियोजनाएं वर्तमान में निर्माण के उन्नत चरण में हैं। इनसे वित्तीय वर्ष 2024 के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है।

उद्योग और वाणिज्य विभाग भारत के निर्यात मानचित्र में असम के उत्पादों की निर्यात क्षमता का दोहन करने के लिए प्रचार गतिविधियाँ चला रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, असम ने फलों, सब्जियों, मसालों, चावल, शहद आदि सहित लगभग 4,000 करोड़ रुपये के विकर हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों का सफलतापूर्वक निर्यात किया गया है।

एक जिला एक उत्पाद में असम की भागीदारी उल्लेखनीय रही है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1984 करोड़ रुपये की असम चाय (रूढ़िवादी, सीटीसी आदि सहित) और 2.24 करोड़ रुपये के रेशम के सफल निर्यात सहित प्रमुख उपलब्धियां शामिल हैं। ये दोनों उत्पादों को जीआई टैग मिला हैं और वैश्विक स्तर पर बाजार प्राप्त करने में सक्षम हुआ है। असम में 11 वस्तुओं को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जैसे असम

चाय, असम रेशम, जोहा चावल, असम नींबू, कार्बी आंगलोंग अदरक, आदि।

ईओडीबी के तहत सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल का विस्तार 20 विभागों और 38 उप-विभागों से 228 सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया है। आज तक 17,92,947 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं और 99.18% का निपटारा हो चुका है।

हमारी सरकार बड़े उत्साह के साथ स्टार्ट-अप प्रयासों की क्षमता की सराहना करती है। हमने गुवाहाटी में एक अत्याधुनिक इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किया है। कुल 257 स्टार्टअप इनक्यूबेट किए गए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में स्टार्टअप्स द्वारा उत्पन्न 33 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व के साथ 74 करोड़ रुपये से अधिक बाहरी फंड जुटाया गया है। 272 MASI मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स द्वारा 4,99,80,000 रुपये का अनुदान उत्पन्न किया गया।

मुख्यमंत्री का आत्मनिर्भर असम अभिजन (सीएमएएए) एक दूरदर्शी पहल है जो बेरोजगारी को लक्षित करती है और उद्यमियों के लिए स्व-रोज़गार के अवसर प्रदान करके असम में समावेशी विकास को बढ़ावा देती है। इस योजना के माध्यम से अगले 2 वर्षों में 2 लाख पात्र लाभार्थियों को लक्षित किया जाना है। वित्त वर्ष 2023-24 में चयनित एक लाख पात्र लाभार्थियों को 2 लाख रुपये (सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए) और 5 लाख रुपये (इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, बीडीएस आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में आवेदकों के लिए) मिलेंगे।

यह योजना 23 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी और 7 नवंबर 2023 तक कुल 2,29,145 आवेदकों ने पंजीकरण कराया था। 8 दिसंबर 2023 को, CMAAA के लिए "आवेदन प्रस्तुत करना" लॉन्च किया गया

था जिसमें पंजीकृत आवेदकों को अपने व्यावसायिक प्रस्ताव जमा करने की आवश्यकता होती है। 1 जनवरी 2024 तक, कुल 21,587 आवेदकों ने पोर्टल के माध्यम से CMAAA आवेदन जमा किया है।

उद्योग, वाणिज्य और पीई विभाग 17 सितंबर, 2023 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू कर रहा है। यह योजना शुरू करने के बाद से असम द्वारा 4 लाख से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं, जो भारत में चौथा सबसे अधिक है। कवर किए गए पांच प्रमुख व्यवसाय राजमिस्त्री, दर्जी, बढ़ई, फिशनेट निर्माता, टोकरी निर्माता हैं। इसके अलावा, 25,000 से अधिक लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है और उन्हें योजना के लाभ के लिए अनुशंसित किया गया है। राज्य की 2,024 ग्राम पंचायतों में से 1,443 ग्राम पंचायतें अब तक इसमें शामिल हो चुकी हैं।

एमएसएमई हमारे राज्य के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ है। जुलाई 2020 में उदयम पोर्टल शुरू करने के बाद से, असम में पंजीकृत एमएसएमई की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। उद्यम पोर्टल ने अब 1 जनवरी 2024 तक 3,77,169 एमएसएमई को पंजीकृत किया। वर्ष 2023 में, 9,56,803 कर्मचारियों के साथ लगभग 1,43,537 एमएसएमई ने एमएसएमई उद्यम पोर्टल में नए पंजीकरण कराए। इसके अलावा, नई दिल्ली में आयोजित आईआईटीएफ 2023 में असम पवेलियन ने रजत पदक जीता।

पर्वतीय क्षेत्र विभाग -

कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (केएएसी) और एन.सी. हिल्स स्वायत्त परिषद (एनसीएचएसी) को राज्य सरकार के नोडल विभाग के

रूप में पहाड़ी क्षेत्र विभाग द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। वर्तमान सरकार असम के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थायी शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों स्वायत्त परिषदों को उनके विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा पहले से ही अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है।

महत्वपूर्ण गतिविधियाँ और उपलब्धियाँ:

कार्बी आंगलोंग के दीफू के तारालांगसो में, असम में 3000 से अधिक लोगों की सुविधा वाले मीटिंग हॉल का निर्माण किया गया।

कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (केएएसी) ने सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत केएएसी को आवंटित फंड से 100.00 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रमुख परियोजनाओं में से एक 12.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर दीफू में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल है। परियोजना लगभग पूरा हो चुका है।

महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए 44 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र निर्माणाधीन हैं और जनवरी, 2024 के भीतर पूरा होने की संभावना है।

कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित आगामी योजनाएं दीफू मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया जाएगा। मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी, चांदमारी के कार्यालय से दीफू स्टेडियम से दीफू प्रधान डाकघर तक एक फ्लाईओवर निर्माणाधीन है।

एनसीएचएसी पर्यटन के बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, पर्यटन स्थलों के विकास और रखरखाव में सुधार, नए अस्पष्ट पर्यटक स्थलों को

विकसित करने, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सर्किट दोनों के लिए स्वदेशी त्योहारों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी प्रयास सी जा रही है।

वर्तमान सीईएम के युवा और गतिशील नेतृत्व के तहत, एनसीएचएसी जिले में आशा कार्यकर्ताओं को स्कूटी और बढ़ा हुआ पारिश्रमिक प्रदान करने जैसे कई नवीन पहल की जा रही है।

हाफलोंग सिविल अस्पताल में आईसीयू और डायलिसिस केंद्र की स्थापना की जा रही है।

जिले के गरीब छात्र समुदाय के बीच महत्वाकांक्षी सिविल सेवकों के लिए सुपर 30 कोचिंग सेंटर का निर्माण की जा रही है।

परिषद में आने वाले बीपीएल व्यक्तियों को निःशुल्क दोपहर का भोजन की व्यवस्था की जा रही है। गांव बुढ़ा का पारिश्रमिक बढ़ाया गया।

युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र की स्थापना।

प्रथागत कानून न्यायालय की स्थापना।

स्थायी आवासीय प्रमाणपत्र (पीआरसी) का डिजिटलीकरण आदि की जा रही है।

जिले के सभी 28 एमएसी निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय विकास समिति (सीएलडीसी) कार्यालयों की स्थापना की जा रही है।

एएमएआई नामक एक नई योजना की शुरूआत जिसके द्वारा सीजेरियन सेक्शन से गुजरने वाली बीपीएल महिलाओं को 10,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, एमओएस के तहत परियोजनाएं कार्बी आंगलोंग और एन.सी. हिल्स की दोनों स्वायत्त परिषदों द्वारा भी कार्यान्वित की जा रही हैं।

हथकरघा कपड़ा और रेशम उत्पादन क्षेत्र -

असम में, हथकरघा बुनाई असमिया संस्कृति और विरासत से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। असम का हथकरघा उद्योग कृषि के बाद महत्वपूर्ण रोजगार प्रदान करता है। यह शिल्प कौशल पीढ़ीगत विरासत का अनमोल हिस्सा है और इसे असम में प्राचीन काल से बुनाई की सदियों पुरानी परंपरा में लगे कुशल बुनकरों द्वारा जीवित रखा गया है।

मेरी सरकार निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:-

स्वानिर्भर नारी :-

राज्य सरकार बुनकरों के आर्थिक उत्थान के लिए 33 पारंपरिक हाथ से बुनी हुई वस्तुओं जैसे- गामोचा, अरोनाई, मिसिंग डूमर और ए'रकोग, राभा पाजार, कार्बी-पोहो, मणिपुरी खुदेई, दिमासा रिसा बासा, तिवा फली, देउरी गमोचा, कोच राजबोन्शी गमोचा आदि की खरीद करके एक प्रमुख योजना स्वानिर्भर नारी लागू कर रही है। यह 2022-23 से बिचौलियों के हस्तक्षेप के बिना एक ऑनलाइन पोर्टल swanirbhar.assam.gov.in के माध्यम से सीधे बुनकरों से खरीदी जा सकती है। विभाग ने पंजीकृत बुनकरों से बेंचमार्क गुणवत्ता वाले उत्पाद खरीदने के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों में अलग-अलग खरीद केंद्र स्थापित किए थे। अब तक 564811 बुनकरों को स्वानिर्भर नारी पोर्टल में पंजीकृत किया गया है और 14573 बुनकरों से 15,02,27,720/- रुपये की कुल 410333 उत्पाद खरीदे गए हैं।

काजीरंगा में एकीकृत हथकरघा पार्क:-

हमारी सरकार ने 56.18 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ बोरजुरी, काजीरंगा, जिला गोलाघाट में 'एकीकृत हथकरघा पार्क' परियोजना को मंजूरी दी है। काजीरंगा में एकीकृत हथकरघा पार्क का उद्देश्य उच्च अंत हथकरघा कपड़े की वस्तुओं के उत्पादन की सुविधा प्रदान करना है, जो हथकरघा परिधान और कपड़े के डिजाइन में विश्व फैशन के अनुकूल है, हथकरघा विरासत का प्रदर्शन, हथकरघा संग्रहालय में प्रदर्शित करना, पर्यटकों को लाइव बुनाई प्रक्रियाओं और रेशम उत्पादन का प्रदर्शन करना है। स्थानीय बुनकरों के लिए विपणन के अवसरों का सृजन किया गया है।

कामरूप जिले के सुआलकुची में मेगा हैंडलूम क्लस्टर:-

वस्त्र मंत्रालय ने 4266 बुनकरों को कवर करते हुए 3241.21 लाख रुपये की परियोजना लागत के साथ कामरूप जिला के सुआलकुची में 'मेगा हैंडलूम क्लस्टर' परियोजना की स्थापना के लिए मंजूरी दी है। सुआलकुची में इस मेगा हैंडलूम क्लस्टर का उद्देश्य ग्राहकों की मांग का जवाब देने के लिए बुनकरों की तैयारी और तकनीकी क्षमता को मजबूत करना और हथकरघा बुनाई से आय का नियमित स्रोत प्रदान करना है।

विभाग लगभग 3.10 लाख रेशम उत्पादन किसानों को भी व्यापक सेवा प्रदान कर रहा है जो रेशम उत्पादन गतिविधियों में शामिल हैं और स्थायी आजीविका प्रदान करने और राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हैं। शहतूत यार्न बैंक के माध्यम से 30% रियायती दर पर शहतूत यार्न उपलब्ध कराकर सुआलकुची के 4299 बुनकरों को समर्थन देना।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र वस्त्र प्रोत्साहन योजना (एनईआरटीपीएस) के तहत एरी स्पन सिल्क मिल, बिस्वनाथ के लिए सिविल निर्माण कार्य 50% प्रगति पर है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से विभिन्न सरकारी विभागों में 25 हेक्टेयर भूमि पर 25 अमृत सरोवर स्थापित किए गए हैं। सेरीकल्चर फार्म जो सर्दियों/शुष्क मौसम के दौरान पौधों को रसीला बना देगा जिससे पत्तियां रेशमकीट के खाने के लिए उपयुक्त हो जाएंगी।

सहकारिता विभाग -

सहकारी समितियों ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, समुदायों को सशक्त बनाने और विभिन्न क्षेत्रों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करके सदियों से हमारे समाज के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को आकार देने में अपरिहार्य भूमिका निभाई है।

बारदाना और जूट खरीद की कमी को दूर करने की दिशा में भी पहल की जा रही है। नलबाड़ी जिले में एक जूट मिल स्थापित करने की तैयारी की गई है। इसके अतिरिक्त, गुवाहाटी के कुमारपारा और नागांव के सेनचोवा में दो पूर्ण महिला सहकारी बाजारों की स्थापना दो पूर्ण महिला सहकारी बाजारों की स्थापनी की गई है। प्रति दिन 10 लाख लीटर दूध का उत्पादन करने, डेयरी क्षेत्र में क्रांति लाने और अनगिनत किसानों के जीवन में सुधार लाने के लिए असम सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एक अभूतपूर्व सहयोग, नॉर्थ ईस्ट डेयरी एंड फूड्स लिमिटेड बनाया गया है।

डिजिटलीकरण और दक्षता की हमारी खोज में, 808 कार्यात्मक पीएसीएस में से 583 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) कम्प्यूटरीकरण के दौर से गुजर रही हैं। सहयोग मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी-एसपीवी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन पीएसीएस को सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के रूप में उपयोग करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा, प्राथमिक कृषि ऋण समिति को असम में 428 स्थानों पर खुदरा पेट्रोल/डीजल दुकानों के आवंटन के लिए संयुक्त श्रेणी 2 (सीसी2) में प्रवेश दिया गया है, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में सहकारी भागीदारी के लिए नए रास्ते खुल गए हैं। स्वास्थ्य देखभाल और कृषि के प्रति हमारी प्रतिबद्धता जेनेरिक दवाओं और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ जमीनी स्तर पर कृषि और उर्वरक से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों और प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (पीएमकेएसके) के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समिति को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सरकार ने सहकारी क्षेत्र से बीज की खेती और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत दो शीर्ष बहु-राज्य सहकारी समितियों की स्थापना की है। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) और राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल)। मिशन अमृत सरोवर, 68 सहकारी समितियों को कवर करते हुए 14 जिलों में भूमि आवंटित करने के साथ, अपने उद्देश्यों की दिशा में आगे बढ़ रहा है। "एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी)" एक अनोखी पहल है। बाक्सा जिले में विशेष शहद उत्पादन इसका एक सफल उदाहरण है।

मत्स्य पालन विभाग -

असम राज्य नदियों, तालाबों, परित्यक्त जल निकायों और बील, आर्द्रभूमि के साथ मत्स्य उत्पादन के लिए एक बेहतरीन स्थान है। यहां नदी के मत्स्य पालन के अलावा, 2.50 लाख हेक्टेयर से अधिक के कुल जल प्रसार क्षेत्र में मत्स्य उत्पादन के लिए उपयोगी है। यह राज्य विविध मछली-जीवों से भी समृद्ध है, जिसमें 216 मीठे पानी की प्रजातियाँ और 200 से अधिक सजावटी प्रजातियाँ उपलब्ध हैं।

मत्स्य पालन और जलीय कृषि रोजगार, पोषण और आजीविका प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2022-23 के दौरान राज्य में मछली उत्पादन 4.43 लाख मीट्रिक टन के स्तर पर पहुंच गया है।

मत्स्य पालन विभाग प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई), विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एपार्ट परियोजना, नाबार्ड सहायता प्राप्त ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि (आरआईडीएफ) और राज्य सरकार के तहत विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष के लिए विभिन्न गतिविधियों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर रहा है।

पीएमएमएसवाई के तहत, प्रत्येक वर्ष 21000 मछुआरों को मछली पकड़ने की प्रतिबंधित अवधि के दौरान सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों को आजीविका और पोषण संबंधी सहायता के लिए 3000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, भारत सरकार ने 106 मछली बीज हैचरी, 740 हेक्टेयर मछली बीज पालन तालाब और 1175 हेक्टेयर नए मछली तालाबों को मंजूरी दी है, जो राज्य में लगभग 1500 मिलियन फ्राई और

लगभग 5500 मीट्रिक टन टेबल मछलियों के अतिरिक्त उत्पादन में योगदान देंगे।

आने वाले वर्षों में पीएमएमएसवाई के तहत प्रमुख घटकों में नए तालाबों का निर्माण, मछली पालन में इनपुट सहायता, मछली मूल्य वर्धित उद्यम, मछली पकड़ने पर प्रतिबंध अवधि के दौरान मछुआरे परिवारों को आजीविका और पोषण संबंधी सहायता आदि शामिल होंगे। राज्य के मछली उत्पादन की कुल टोकरी में 23 और 16 मौजूदा विभागीय फार्मों के कायाकल्प के साथ-साथ मछली उत्पादन भी शामिल है। मत्स्य विभाग राज्य के बाहर से आने वाली सभी मछलियों का फॉर्मेलिन परीक्षण करने की भी पहल कर रहा है, जिसमें स्थानीय रूप से उत्पादित मछलियां भी शामिल हैं जो थोक बाजार में पहुंचती हैं। इसके अलावा, सभी हितधारकों विशेषकर किसानों के लिए व्यापक जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) -

असम सरकार ने दिसंबर, 2015 से राज्य में "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम", 2013 लागू किया है। आज तक 2,34,36,008 आबादी वाले कुल 66,61,896 परिवारों को एनएफएसए के तहत कवर किया गया है। इनमें से 6,74,976 अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और 59,86,920 प्राथमिकता घरेलू (पीएचएच) परिवार हैं। एएवाई परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम चावल और पीएचएच परिवारों को प्रति माह प्रति परिवार के सदस्य को 5 किलोग्राम चावल मुफ्त प्रदान किया जाता है।

जनवरी, 2024 से एनएफएसए के मौजूदा लाभार्थियों में 10,73,489 नए राशन कार्ड धारकों को शामिल करते हुए कुल 42,85,745 नए लाभार्थियों को शामिल किया गया हैं।

राज्य में खाद्यान्न का उचित वितरण सुनिश्चित करने और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की निगरानी प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए हर महीने की पहली से 10 तारीख तक अन्न सेवा दिवस मनाते हुए मुफ्त चावल का वितरण किया जाता है।

असम सरकार ने प्रमाणित लाभार्थी को अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी एफपी दुकान से खाद्यान्न उठाने में सक्षम बनाने के लिए राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना (ओएनओआरसी) लागू की है।

असम सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) परियोजना के एंड टू एंड कम्प्यूटरीकरण के एक भाग के रूप में सभी चयनित लाभार्थियों के डेटा और जीपीएसएस/एफपी शॉप डेटा को डिजिटलीकरण किया है। जीपीएसएस स्तर तक इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है और राज्य पारदर्शिता पोर्टल www.pds.assam.gov.in को विकसित किया गया है। शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गई है। इस संबंध में, टोल फ्री नंबर 1800-345-3611 और 1967 (बीएसएनएल उपयोगकर्ताओं के लिए) के साथ आयुक्त, एफसीएससीए और एलएम, असम के कार्यालय में कॉल सेंटर स्थापित किया गया है।

असम सरकार "आमार दुकान" के माध्यम से उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर 22 गैर पीडीएस एमआरपी आधारित वस्तुएं प्रदान कर रही है। वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिलों में 5623 "आमार दुकान" कार्यरत हैं। वर्ष 2023-24 के लिए 206 "आमार दुकान" को वित्तीय

सहायता प्रदान की गई है। 14 जिलों को कवर करने वाले कुल 115 एफपीएस ने आईओसी वितरक के रूप में 5 किलोग्राम एफटीएल एलपीजी सिलेंडर की बिक्री शुरू कर दी है। असम सरकार राज्य भर के विभिन्न बाजारों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर लगातार निगरानी रख रही है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारी विभिन्न बाजारों का दौरा कर रहे हैं और थोक और खुदरा दोनों स्तरों पर बाजार कीमतों की पुष्टि कर रहे हैं।

असम सरकार ने धान खरीद कार्यक्रम के तहत धान किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान किया है। चालू केएमएस में राज्य ने 169 पीपीसी (धान खरीद केंद्र) के माध्यम से 7.04 एलएमटी खरीद का लक्ष्य रखा है। दो जिले अर्थात-बिश्वनाथ और बोगाईगांव जिले को धान खरीद के विकेंद्रीकृत कार्यक्रम (डीसीपी) मोड को अपनाने के लिए चुना गया है। धीरे-धीरे, सरकार समय-समय पर पूरे राज्य को धान खरीद के डीसीपी मोड के दायरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। असम खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने निम्नानुसार कई उदार सब्सिडी उन्मुख कार्यक्रम योजनाएं शुरू की हैं। जैले-मिलिंग क्षमता को 15 एलएमटी/वर्ष तक बढ़ाने के लिए 270 चावल मिलों की स्थापना। यह योजना मिलों की क्षमता के आधार पर सीमा के अधीन 50% की अधिकतम सब्सिडी से जुड़ी है। वर्तमान में 170 चावल मिल का काम पूरा हो चुका है।

विधायी विभाग -

विभिन्न प्रशासनिक विभागों की पहल पर विधायी विभाग ने कुल 78 अधिनियम और 09 अधिनियम बनाए हैं। अध्यादेशों का जो वर्ष 2023-2024 के दौरान आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

असम कानूनी सेवा प्राधिकरण ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों के साथ मिलकर कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के लक्ष्य और उद्देश्य तक पहुंचने के लिए लक्षित लाभार्थियों को कानूनी सहायता प्रदान करना, लोक अदालतों का आयोजन, कानूनी जागरूकता शिविर आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम स्थापित किया है।

इसके अलावा, असम राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में एससी, एसटी, महिलाओं, बच्चों, विकलांग व्यक्तियों, औद्योगिक श्रमिकों और अन्य लोगों की कुल 43,447 को, जिनकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है, उन्हें असम के मार्गदर्शन में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा कानूनी सेवाएं प्रदान की गई है।

वर्ष 2023 (जनवरी से दिसंबर) के दौरान, राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कुल 693021 मामले निपटान के लिए उठाए गए, जिनमें से 121848 मामलों का निपटारा 304,21,20,574/- रुपये की समझौता राशि के साथ किया गया। इसके अलावा, तीन (3) विशेष लोक अदालतें क्रमशः बरपेटा (मार्च, 2023), बोंगाईगांव (जुलाई, 2023) और मोरीगांव (अगस्त, 2023) जिले में आयोजित की गईं। विशेष लोक अदालत के माध्यम से कुल 434 मामले समाधान किए गए, जिनमें से 43 मामले 18837897/- रूपये की समझौता राशि पर समाधान किए गए।

वर्ष 2023 (30 नवंबर तक) के दौरान, असम के विभिन्न जिलों के जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों ने पैनल वकीलों के लिए 16 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इसी तरह, बार के सदस्यों, सीडब्ल्यूसी के

सदस्यों, स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों, गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों, पुलिस अधिकारियों, जांच अधिकारियों, गांवबुरहा, कानून के छात्रों, किशोर न्याय बोर्ड के हितधारकों, वन अधिकारियों, ड्राइंग और अन्य के लिए 36 अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम को विभिन्न जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित किए गए थे।

मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हाल के दिनों में मेरी सरकार ने उग्रवाद विरोधी अभियानों, अपराध में कमी, बाल विवाह, नशीली दवाओं की बरामदगी आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। पिछले वर्ष पिछले वर्ष 1249 उग्रवादियों ने 364 हथियार और 2946 राउंड गोला-बारूद के साथ आत्मसमर्पण किया। असम पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ अपना गहन अभियान जारी रखा और 167 किलोग्राम हेरोइन, 30,963.72 किलोग्राम गांजा और अन्य पदार्थ बरामद किए। कुल मिलाकर, असम पुलिस ने 10 मई 2021 से 02 जनवरी 2024 की अवधि के दौरान 1882 करोड़ रुपये की प्रतिबंधित दवाएं और नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। कुल मिलाकर अपराधों की संख्या 2021 में 1,33,239 से घटकर 2023 में 63,713 हो गई। जबकि सजा की दर 2021 में 6.1% से बढ़कर 2023 में 16.69% हो गई।

उल्फा समझौता

दशकों की शत्रुता, रक्तपात और उग्रवाद के अंत को चिह्नित करते हुए, 29 दिसंबर 2023 को उल्फा के साथ शांतिपूर्ण बातचीत के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों का उद्देश्य स्वदेशी समुदायों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हितों की

रक्षा करना, उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना, शांति बहाल करना और राज्य का तेजी से आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है।

बाल विवाह के विरुद्ध कदम

बाल विवाह मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है जो लंबे समय तक चलने वाले शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक आघात का कारण बनता है। इस संबंध में, प्रासंगिक कानूनों के तहत विशेष अभियान शुरू किए गए हैं और 8,800 से अधिक आरोपियों के खिलाफ 5347 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 4,407 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पहली बार इस समस्या से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास किया गया है।

ग्राफ्ट से निपटना

लोक सेवकों द्वारा रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए पिछले कैलेंडर वर्ष में 91 ट्रैप मामलों को सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया। इस कार्यवाही के दौरान 117 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 45 अधिकारियों सहित 103 लोक सेवक हैं। इसी तरह, आर्थिक अपराध जांच ब्यूरो ने अपना अभियान चलाया है और जीएसटी धोखाधड़ी, बैंक धोखाधड़ी, एनबीएफसी, हेराफेरी से संबंधित मामले दर्ज किए हैं और 25 लोक सेवकों सहित 88 लोगों को गिरफ्तार किया है।

रोजगार क्षेत्र

सरकारी क्षेत्र में रोजगार के संबंध में, मेरी सरकार ने 31 जनवरी 2024 तक एक लाख के लक्षित आंकड़ों में से राज्य के लगभग 88,547

बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया है और वर्ष 2024-2025 के दौरान लक्ष्य पूरा करने की उम्मीद की जा रही है।

माननीय सदस्यगण, मैंने अपनी सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। हमारी सरकार असम के लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले बताई गई नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा की झलक से यह पता चलता है कि हमारी सरकार अगले दो वर्षों में किस दिशा में जाने का प्रस्ताव रखती है। मैं इस सदन से राज्य के सर्वांगीण विकास और असम के लोगों के सभी वर्गों के लाभ के लिए समर्थन और मिलकर काम करने का अनुरोध करता हूं।

जय हिन्द

******

2024

असम सरकार मुद्रणालय

गुवाहाटी-21